04 - शिक्षा बनाम सत्ता- हार्वर्ड की हुंकार

05 - भारत की चुनाव प्रणाली ने वैश्विक स्तर पर पाई प्रामाणिकता

A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 21 अप्रैल, 2025

06 - बुजुर्ग शांति बाई को कलेक्टर ने दिलाया न्याय, वर्षों पुरानी...

07 - मनावर में बारातियों से भरी बस पलटी, महिला की मौत,12 लोग...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 221, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

पहली बात

आईजेआर-2025: राग-दरबारी की 'लंगड़' की तरह 'लंगड़ा' न्याय

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

इन दिनो, जबकि भारत की सर्वोच्च अदालत याने सुप्रीम कोर्ट उपराष्टपति जगदीप धनखड़ सहित कतिपय भाजपा सांसदों के सवालों के निशाने पर है, देश की निचली अदालतों की देहरी पर खड़े हजारों-लाखों 'लंगड़' यतीमों की तरह न्याय के लिए भटक रहे हैं। भारत की दूषित न्याय व्यवस्था का यह चेहरा 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 ' के ताजा संस्करण में सामने आया है। न्याय का यह परिदृश्य चिंताजनक है। रिपोर्ट कहती है कि वंचित और गरीब वर्ग के भारतीय की न्याय तक पहुंच बहुत ही सीमित है।

न्याय के स्याह बैक-ड्रॉप में 'लंगड़' सांकेतिक है। लंगड याने देश के पच्चीस-तीस करोड़ वो लोग, जो न्याय की तलाश में दुरूह जिंदगी जी रहे हैं। संविधान की ओर आस भरी उम्मीदो से देख रहे हैं।'लंगड़' श्रीलाल शुक्ल के प्रसिध्द उपन्यास राग-दरबारी का वह पात्र है, जिसे एक दीवानी मुकदमें के सिलसिले में एक पुराने मुकदमे की नकल लेने के लिए ताउम्र जूझता दिखाया गया है। न्याय के लिए 'लंगड़' का यह संघर्ष कथानक के पूर्वार्द्ध से उत्तरार्ध तक आखिर पन्ने तक चलता रहता है। उपन्यास में दर्ज 'लंगड़' का रेखाचित्र ग्रामीण भारत के देहातियों का मार्मिक रेखांकन है, जिनके लिए न्याय-व्यवस्था आपदा का सबब है। राग दरबारी में 'लंगड़' का चित्रांकन कुछ इस प्रकार है- ''माथे पर कबीर पंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आँधी पत्ती झेला हुआ दढ़ियल चेहरा, दुबली-पतली देह, मिर्जई पहने हुए...एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी...चेहरे पर पुराने जमाने उन ईसाई संतों का भाव, जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर सौ कोड़े मारते हों''...।

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के निष्कर्षों में भारत की न्याय-व्यवस्था की सेहत राग दरबारी के 'लंगड़' की तरह ही अपाहिज, बीमार, लंगडी बैसाखियों पर टिकी नजर आ रही है। रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट और सामाजिक संगठनों के एक समूह ने हाल ही में जारी की है। समूह ने 24 मानकों के आधार पर विभिन्न राज्यों की न्याय-व्यवस्था का आकलन किया है। भारत की सभी छोडी-बड़ी अदालतों में सवा पांच करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मुकदमों की संख्या अस्सी हजार है। इकसठ हजार से प्रकरण भारत के 25 हाईकोर्ट में लंबित हैं और जिला न्यायालयों में इनकी चौंकाने वाली संख्या साड़े चार करोड़ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अप्रेल 2024 तक भारत की जेलों में पांच लाख तीस हजार विचाराधीन कैदी अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे।

लंबित मुकदमों और विचाराधान कैदियों की संख्या से स्पष्ट है कि देश की लगभग एक चौथाई आबादी न्याय के लिए भिन्न-भिन्न किस्मों की प्रताड़नाओं से गुजर रही है। कचहरी के चक्करों का अंतहीन कुचक्र उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि फैसलों की मियाद का कोई सिरा उनके पास नही है। भारत में न्याय पर बहुत ही समय और धन व्यय होता है। भारत में लंबित मामलों की मियाद के अंतिम सिरे पर पहुंच पाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय अदालतों में एक मामले की लंबित रहने की औसत मियाद करीब तीन से पांच बरस मानी जाता है। कुछ मामलों में मियाद की उम्र कई दशकों लंबी हो जाती है। न्यायालय में चलने वाले मुकदमों में सनी देओल की फिल्मी डॉयलॉग 'तारीख पर तारीख...तारीख पर तारीख' यूं ही लोगों के जहन में चस्पां नहीं हुआ है। यह लंबी मियाद न्याय की प्रक्रियाओं में अविश्वास का सबब भी है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के सार परेशान करने वाले हैं। सारांश यह है कि मौजूदा न्याय व्यवस्था अधिकांशतः आम जनता सुसंगत, समाधानकारक सामयिक न्याय देने के मामले में सक्षम और समर्थ सिध्द नहीं हुई है। यह रिपोर्ट न्याय व्यवस्था के चार स्तंभों पुलिस, न्याय पालिका,जेल और विधिक सहायता से संबंधित 24 मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों को मानको के आधार पर तौला गया है। इन मानको की कसौटियो पर कोई भी राज्य यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उसके यहां पूर्ण सुचारू और व्यवस्थित न्याय-व्यवस्था है। देशमें प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 182 रूपए प्रति व्यक्ति न्याय-पालिका पर खर्च किए जाते हैं। जबकि कानून सहायता पर यह खर्च 6.46 रूपए प्रति व्यक्ति है।

यह रिपोर्ट न्याय में होने वाली शिथिलता और देरी के कारणों की ओर भी इशारा करती है। लंबित मामलों के इंडेक्स में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण न्यायालयों में सभी स्तरों पर जजों की कमी है। देश में जजों की कुल संख्या लगभग 21000 है। संख्या के मान से भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 15 जज नियुक्त है, जबकि विधि आयोग की सिफारिशें कहती हैं कि यह आंकड़ा 500 होना चाहिए।

फिलवक्त देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 33 फीसदी पद रिक्त पड़े है। जिला न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या 21 प्रतिशत है। जजों की कमी की वजह से पेंडिंग केसेस की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिला अदालतों में एक जज के पास औसतन 2200 मुकदमों का बोझ है। मध्य प्रदेश हायकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो एक जज के पास 15000 केसेस पेंडिंग हैं। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 थी, जो स्वीकृत पदों से दो कम थी।

पुलिस के मामले में भी रिपोर्ट संतोषजनक नही हैं। पूरे देश में 28 फीसदी अधिकारियों की कमी है। आबादी के मान से प्रति एक लाख आबादी पर 120 पुलिस बल उपलब्ध है, जबकि वैश्विक मापदंड प्रति एक लाख पर 222 है। हर 831 लोगों के पीछे एक पुलिस बल होना चाहिए।

चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि भारत की जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा याने 131 फीसदी कैदियों का भार वहन कर रही हैं। इनमें 76 फीसदी कैदी विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट कई मर्तबा कह चुका है कि विचाराधीन एक खास अवधि से ज्यादा समय तक बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया को तेज किया जाए। लेकिन यह काम नहीं हो पा रहा है। इसकी एक वजह जेलकर्मियों की कमी है। देश की जेलों में 30 फीसदी पद रिक्त पडे हैं।

रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि मौजूदा न्याय व्यवस्था संविधान में अन्तर्नीहित सामाजिक और लैंगिक समता के उद्देश्यों पर पूरी तरह साबित नहीं हो सकी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में पहली बार जारी की गई थी। यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय साविधिक रिपोर्टिंग है, जो राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमताओं को रैंक प्रदान करती हैं। रिपोर्ट कहती है कि निचले स्तर पर कानून और संविधान की समझ में कमतरी न्याय की राहों में सबसे बड़ा अवरोध है। संविधान और कानून के प्रति नकारात्मकता, निरादर और नासमझी न्याय की कमजोरी का चिंताजनक पहलू है।

सुप्रभात

किसी दिन बारिश किसी दिन सूखा रहता है
मौसम का मिज़ाज यूँही बदलता रहता है।
हरकतों से उसकी अच्छी तरह वाकिफ हूँ
सबके सामने वह सीधा सादा रहता है।
नफरतों के बाजार में एक तीली काफी है
मोहब्बत का दरिया मगर बहता रहता है।
सताता है ख्वाबों में अक्सर वो रात दिन
मेरी यादों में एक भोला चेहरा रहता है।
बिक चुका सारा सामान खाली है मकान
बेवजह हमारी गली में आता जाता रहता है।
कुछ न कुछ कमी रहती है मुकम्मल इंसां में
चाँद भी कभी पूरा कभी आधा रहता है।
आँखों ने महसूसा तुम्हे छूकर आती हवा को
इसी वजह फिजा का दामन महका रहता है।
बातें सिर्फ खयालों में सिमटे तो अच्छा
ख्वाबों के महल में कोई तो अपना रहता है।
सुना है उसके घर में चाँद उतर आया है
घर की खिडकियों पर सदा पर्दा रहता है।

– डॉ.निशिकांत कोचकर

अब मतदाता सूची को साफ सुथरा करेगा चुनाव आयोग

डुप्लीकेसी हटाने के लिए चलाएगा अभियान,शुरुआत बिहार चुनाव से होगी

- 22 करोड़ वोटर्स आधार से लिंक नहीं,बीएलओ घर-घर वेरिफिकेशन करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग (ईसी) वोटर्स लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कवायद करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसकी शर्त को पूरा करने के लिए उन वोटर्स से कारण जानना जरूरी है, जिन्होंने अभी तक अपना

आधार नंबर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया है। आयोग के पास अभी तक 66 करोड़ मतदाताओं के आधार एपिक नंबर (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर) से लिंक्ड हुए हैं, लेकिन अब भी करीब 22 करोड़ मतदाताओं के आधार उपलब्ध नहीं हैं। इसका नतीजा ये है कि आधार के बेस पर मतदाता सूची से डुप्लीकेशन खत्म करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूचियों से डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए वोटर्स तक पहुंचने की योजना बनाई गई है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारियों को सक्रिय किया जाएगा, जो मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करेंगे। इस दौरान पता लगाया जाएगा कि अगर एपिक नंबर को आधार से लिंक किया गया है तो उसकी पुष्टि क्यों नहीं की। अगर लिंक नहीं किया है तो उसकी वजह जानी जाएगी। बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) अपना संपर्क नंबर वोटर्स के साथ शेयर करेगा।

आज से भारत के चार दिवसीय दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति

- दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल 21 अप्रैल को भारत के चार दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर आएंगे। वे इटली का दौरा कर भारत आ रहे हैं। सोमवार सुबह 10 बजे जेडी वेंस दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद वे अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे।

भारत-फ्रांस 28 अप्रैल को साइन करेंगे 26 राफेल-मरीन जेट डील

- 64 हजार करोड़ में फाइनल हुई,दोनों देशों के बीच यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और फ्रांस 28 अप्रैल को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। डील पर साइन फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू की मौजूदगी में होंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 64 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की डील पर साइन करते समय दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। यह कार्यक्रम साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर भी आयोजित करने की योजना है। फ्रांसीसी मंत्री का 27 अप्रैल की शाम को भारत पहुंचने और अगले दिन लौटने का शेड्यूल है। गौरतलब है कि भारत ने 9 अप्रैल को गवर्नमेंट-टु-गवर्नमेंट डील के तहत पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फ्रांस के साथ 26 राफेल-मरीन लड़ाकू विमानों के लिए सौदे को मंजूरी दी थी। इस सौदे में 22 सिंगल-सीटर, 4 ट्विन-सीटर जेट शामिल होंगे। साथ ही बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा।

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भीषण तबाही

रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत,100 लोगों का रेस्क्यू

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया। सूत्रों ने बताया कि बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसके चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर, रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़-पद्दर मार्ग भी बंद है। यहां वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। लैंडस्लाइड के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरते देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। एक वीडियो में तीन-चार टैंकर और कुछ अन्य गाड़ियां मलबे में पूरी तरह दबी हुई दिख रही हैं। इसके अलावा होटल और घर भी मलबे से प्रभावित दिख रहे हैं। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, 25-30 घरों में भी नुकसान हुआ है। धर्मकुंड पुलिस ने करीब 90-100 लोगों को सुरक्षित बचाया। उधमपुर जिले की सतैनी पंचायत में भी तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पंचायत के पूर्व सरपंच पर्शोत्तम गुप्ता ने बताया कि इलाके में कई पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात और बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा- मैंने अपनी पंचायत का निरीक्षण किया है। कई पेड़ गिर चुके हैं और बिजली की आपूर्ति ठप है। पिछले 4-5 सालों में इतनी तेज हवाएं पहली बार देखी हैं।

ट्रंप के खिलाफ अमरीका के सभी राज्यों में प्रदर्शन

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी ट्रम्प की टैरिफ वॉर की नीतियों, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रम्प पर नागरिक और कानून के शासन को

कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50501 नाम दिया गया है, जिसका मतलब '50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, 1 आंदोलन' है। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूमों का भी घेराव किया। ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शनों का यह दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रम्प के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कारोबारी इलॉन मस्क की आक्रामक नीतियां हैं।

मंदसौर-नीमच जिले में एक भी खेत नहीं रहेगा सिंचाई से वंचित - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

महर्षि सांदीपनि विद्यालय का उद्घाटन कर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए

मंदसौर/नीमच/जावद (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को नीमच जिले के जावद में महर्षि सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने रामपुरा में 14 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।

37.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विद्यालय में करीब 1700 विद्यार्थी पढ़ेंगे। यह विद्यालय प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2022-23 में सीएम राइज स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। अब इसे महर्षि सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच के जावद में सांदीपनि विद्यालय (सीएम राइज स्कूल) के लोकार्पण समारोह में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर और नीमच जिले के हर खेत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश को दी गई दो बड़ी राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना से पूरा मालवा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। किसानों को सोलर पम्प देकर उन्हें बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जायेगी। किसान अब खुद सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करेंगे। अधिक बिजली उत्पादन होने की स्थिति में किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी।

मुख्यमंत्री ने किया सुविधि रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट मोरवन, का भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुविधि रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड का भूमि-पूजन किया। इस परियोजना से नीमच को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह परियोजना 31 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित की जाएगी, जिससे लगभग 2000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह इकाई 'फार्म टू फैशन' की अवधारणा को रूप देगी, जिसमें कच्चे माल की खरीद किसानों से लेकर फिनिश्ड फैब्रिक तक की संपूर्ण प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर संपन्न होगी। यह एक पूर्णतः एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा, जिसमें 168 आधुनिक लूम्स, 30,000 स्पिंडल्स और तीन प्रोसेसिंग हाउस स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि सुखानंद तीर्थ स्थल को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। थड़ोद स्थित हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। सिंगोली स्थित स्वास्थ्य केंद्र का परीक्षण कर उन्नयन की कार्यवाही होगी। जावद में स्थित स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तरीय कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एशिया में चीते प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मध्यप्रदेश ने इस प्रोजेक्ट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्राणियों के लिए भी सरकार ने चिंता की है। चीते की मध्यप्रदेश में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। गांधीसागर में वन्य प्राणियों से लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इको सिस्टम अच्छा बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज नागरिकों के लिए बहुत ही खुशियों का अवसर है।
शिक्षा के क्षेत्र में भारी बदलाव हुए हैं। सनातन संस्कृति, कृषि, उद्योग, शिक्षा के लिए सरकार ने काम किया है। साइबर तहसील के माध्यम से सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किये गये। इसके साथ ही चीता आने से गांधी सागर अभयारण्य में पर्यटन की संभावना को नए पंख लगे हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22 °c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ रविवार, 21 अप्रैल 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

इसरो का गजब प्रयोग,अजीब प्राणी को भेजेगा स्पेस

- एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के साथ पहुंचेगा स्पेस,प्रजनन पर करेगा रिसर्च

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक भारतीय एस्ट्रोनॉट अब अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचने वाला है और साथ ले जा रहा है अपने साथ एक ऐसा प्राणी, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मिशन का नाम है ऐक्जिम-4 और भारत के शुभांशु शुक्ला इसमें उड़ान भरने जा रहे हैं। वह न सिर्फ स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे बल्कि वहां रहेंगे, काम करेंगे, और सबसे खास बात कि वो एक बेहद अजीब और टेढ़े-मेढ़े दिखने वाले सूक्ष्म

जीव वोएजर टार्डीग्रेड्स को भी साथ ले जा रहे हैं। इसरो इस अजीब से जीव को स्पेस में क्यों भेज रहा है आइए जानते हैं। इसे वॉटर बीयर यानी 'पानी का भालू' या मॉस पिगलेट भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के देखे नहीं जा सकते। लेकिन यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैं। ये जीव किसी अजूबे से कम नहीं, इसे जल, बर्फ, आग, वैक्यूम, रेडिएशन, यहां तक कि स्पेस की सख्त स्थितियां भी नहीं मार पातीं। इनका शरीर आठ पैरों वाला होता है और उनके पंजों में नन्हें-नन्हें नुकीले नाखून होते हैं। इनके चलने का अंदाज ऐसा जैसे कोई प्यारा भालू धीरे-धीरे डग भर रहा हो। इस प्रयोग में शुक्ला स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक इन टार्डीग्रेड्स के साथ जीने वाले हैं।

बदल गए जज्बात...भारतीय बाजार में कूदे विदेशी निवेशक

तीन दिन में झोंके 15,000 करोड़ रुपए, झूम उठा शेयर बाजार

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी की है। कुछ हफ्तों तक किनारे रहने के बाद तीन दिन में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। लगातार नौ

- फाइनेंस,टेलीकॉम और एविएशन को होगा फायदा,मस्ती में बाजार

दिनों तक बिकवाली करने के बाद यह बदलाव बाजार के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है। इसकी वजह से सेंसेक्स में सिर्फ तीन दिन में लगभग 3,400 अंकों की तेजी आई है। यह हाल के दिनों में सबसे तेज उछाल है। हालांकि इस की खरीदारी के बावजूद निवेशक अब भी अप्रैल में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। महीने के लिए कुल

आउटफ्लो अब भी 18,000 करोड़ रुपये से ऊपर है। लेकिन भारतीय इक्विटी में विदेशी निवेश कई साल के निचले स्तर पर आ गया था। इसलिए अगर बाजार का माहौल ठीक रहता है, तो यह कमी एक और खरीदारी की लहर पैदा कर सकती है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार के अनुसार ने कहा कि निवेशकों की गतिविधि में यह बदलाव दो मुख्य कारणों से हुआ है। पहला, डॉलर इंडेक्स गिरकर लगभग 100 के स्तर पर आ गया है। डॉलर के और कमजोर होने की उम्मीद निवेशकों को अमेरिका से दूर भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर धकेल रही है। दूसरा, अमेरिका और चीन दोनों की विकास दर इस साल कम रहने की संभावना है। वहीं, भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 में 6 फीसदी रहने की उम्मीद है। यह बेहतर प्रदर्शन भारत को वैश्विक पूंजी के लिए एक आकर्षक जगह बना सकता है। निवेशकों का ध्यान घरेलू खपत से जुड़े क्षेत्रों जैसे कि फाइनेंस, टेलीकॉम, एविएशन, सीमेंट, कुछ ऑटो कंपनियों और हेल्थकेयर स्टॉक्स पर रहने की संभावना है। उभरते बाजारों के लिए निवेशकों की पसंद बेहतर होगी।

भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब नए मिशन पर कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी आगामी 25 अप्रैल से देश भर में 'संविधान बचाओ रैली' का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के मुताबिक इन रैलियों का मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े अन्य मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाना है। शनिवार को पार्टी के प्रमुख नेताओं, महासचिवों, प्रभारियों के साथ

कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से कहा है कि इस बैठक में अहमदाबाद में पारित प्रस्ताव 'न्याय पथ संकल्प, समर्पण, संघर्ष' पर चर्चा हुई। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस 'संविधान बचाओ रैली' आयोजित करेगी।

नेशनल हेराल्ड मामले में खरगे ने भाजपा को घेरा

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपपत्र दाखिल किए जाने को साजिश का हिस्सा बताया है। खरगे ने हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं से कहा, आपने गौर किया होगा कि कैसे बड़े षडयंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नाम आरोप पत्र में डाल दिया गया है। पर किसी का भी नाम डाल दें हम डरनेवाले नहीं है। बैठक में खरगे ने पार्टी नेताओं से अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के संदेश को जिला, मंडल, ब्लाक और बूथ तक पहुंचाने की अपील की है।

भिखारियों ने कराई पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती

- सऊदी ने 4700 को पकड़कर भेजा वापस,मंत्री बोले-2 करोड मांग रहे भीख

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया है कि सऊदी अरब ने 4,700 से ज्यादा पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस भेजा है। ये लोग अलग-अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैरकानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। इनको सऊदी पुलिस ने हिरासत में लिया और डिपोर्ट कर दिया। सियालकोट में पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ ने सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों से पकड़ जाने की यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा कब से कब तक का है।

भारत व फ्रांस के बीच 28 को होगा सबसे बड़ा सौदा

63 हजार करोड़ में 26 राफेल-मरीन विमानों की होगी खरीद

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और फ्रांस के बीच 28 अप्रैल को अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है। इसके तहत, भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-मरीन विमान खरीदे जाएंगे। डिफेंस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि यह 63,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पर दोनों पक्षों के सीनियर अधिकारी साइन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह इवेंट डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स के साउथ ब्लॉक के बाहर आयोजित हो सकता है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु रविवार शाम को भारत पहुंचेंगे और सोमवार देर रात वापस लौट जाएंगे। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी। इस दौरान, नई दिल्ली ने 26 राफेल-मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डील को मंजूरी दी, जो सरकार-से-सरकार के बीच होने वाला समझौता है। इस करार में 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर विमान शामिल हैं। साथ में फ्लीट मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का पूरा पैकेज भी होगा। ये फाइटर जेट आईएमएस विक्रांत से ऑपरेट करेंगे और मौजूदा मिग-29 के फ्लीट को सपोर्ट करेंगे। भारतीय वायुसेना के पास पहले से 2016 में साइन किए गए एक अलग सौदे के तहत 36 राफेल विमान हैं, जो अंबाला और हाशिमारा बेस से ऑपरेट होते हैं। 26 राफेल-मरीन की इस डील से भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या 62 हो जाएगी। इस तरह, भारतीय हथियारों में 4.5-प्लस जेनरेशन के विमानों की तादाद बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना जल्द ही मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नया टेंडर जारी करेगी।

'दिल्ली को लंदन-पेरिस जैसी नहीं, इंद्रप्रस्थ बनाएंगे

- रेखा के मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान,कहा-युधिष्ठिर की राजधानी बनाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं। हम देश की राजधानी दिल्ली को युधिष्ठिर की राजधानी जैसी थी, वैसी बनाने का वादा करते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 1111 जीपीएस सिस्टम से लैस

पानी के टैंकरों को रविवार को बुराड़ी स्थित संत निरंकारी मैदान से रवाना करते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज जो आप देख रहे हैं, वह हमारी सरकार के सुशासन और पारदर्शिता मॉडल का परिणाम है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह टैंकर पहले भी चलते थे लेकिन अब टैंकर को ट्रैक भी किया जा सकेगा। पहले टैंकर माफिया शब्द चलता था हमने इसको दिल्ली जल बोर्ड आईटी डैशबोर्ड से जोड़ दिया है। वर्मा ने कहा कि दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। पिछले 10 साल की 'आपदा' की सरकार और 10 हफ्ते की रेखा सरकार आज दिखा रही है कि क्या हो सकता है।

मुर्शिदाबाद हिंसा

बाप-बेटे की हत्या मामले में अब चौथी गिरफ्तारी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक बाप-बेटे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह मामले में चौथी गिरफ्तारी हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुलिताला पुरबापारा निवासी जियाउल शेख के रूप में हुई है। आरोपी 12 अप्रैल से फरार था। शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल और विशेष जांच दल ने शनिवार को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, यह व्यक्ति मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने मृतक के घर तोड़फोड़ करने के लिए भीड़ को उकसाया था और 12 अप्रैल को हरगोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और शेख के मोबाइल फोन लोकेशन से उसका पता लगाया। इससे पहले पुलिस ने दो भाइयों कालू नादर और दिलदार साथ ही एक अन्य आरोपी इंजामुल हक को गिरफ्तार किया था।

राज्यपाल ने पीड़ितों को फोन नंबर उपलब्ध कराया

17 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने के आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 19 अप्रैल को मुर्शिदाबाद का दौरा किया था। राज्यपाल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से भी मिले।

सांसद अमृतपाल पर एक साल और बढ़ा एनएसए

- 23 अप्रैल से होगा लागू, हाईकोर्ट में अपील की तैयारी

अमृतसर (एजेंसी)। खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। एनएसए बढ़ाए जाने को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह अब एक साल और असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे। अमृतपाल सिंह ने 18 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। नया एनएसए 23 अप्रैल से लागू होगा। अगर इसकी अवधि तीसरी बार बढ़ाई जाती है तो परिवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में सिखों के लिए अलग कानून चल रहा है। उन्होंने एनएसए बढ़ाए जाने को लोकतंत्र और खडूर साहिब के मतदाताओं के साथ विश्वासघात बताया। उनका कहना है कि अमृतपाल के जेल में होने के बावजूद राज्य में अपराध और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिससे सरकार का माहौल खराब होने का तर्क गलत साबित होता है। परिवार का आरोप है कि उन्हें एनएसए बढ़ाए जाने की जानकारी नहीं दी गई है।

'सुप्रीम' विरोध, निशिकांत दुबे की बढ़ गईं मुश्किलें

● अवमानना की कार्रवाई के लिए वकील ने लिखा लेटर ● तनवीर ने बीजेपी नेता के बयान को बताया भड़काऊ

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित टिप्पणी करके फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ अधिनियम मामले में एक वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण को लेटर लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। दुबे ने कहा था कि इस देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। अटॉर्नी जनरल को लिखे अपने लेटर में वकील अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है। लेटर में कहा गया, मैं यह लेटर कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई को विनियमित करने के नियम, 1975 के नियम 3(सी) के साथ लिखकर झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र से माननीय लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आपकी विनम्र सहमति मांग रहा हूं, क्योंकि

उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए हैं जो बेहद निंदनीय, भ्रामक हैं और जिनका उद्देश्य भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करना है। दुबे की यह टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद आई है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को सुनवाई के अगले दिन तक लागू नहीं करेगी, क्योंकि न्यायालय ने उन पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने शनिवार को दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना से खुद को अलग कर लिया और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को उनका निजी विचार बताया। नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा का उसके सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना-देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन भाजपा न तो उनसे सहमत है और न ही ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करती है।

पीआरएसआई द्वारा लोक संपर्क सम्मान सहित 24 महिलाओं को अचला/उदिता सम्मान

भोपाल। समाज के अनेक क्षेत्रों में आज एआई का भरपूर उपयोग होने लगा है लेकिन इसका सारा नियंत्रण समाज के ही हाथ में है। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि जहां भी इसका उपयोग करें तो लोकमंगल की भावना के साथ करें। यह बात माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरू विजय मनोहर तिवारी ने रविवार को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के भोपाल चैप्टर द्वारा आयोजित व्याख्यान एवं सम्मान समारोह के दौरान विशेष अतिथि के रूप में कही।

'रिस्पांसिबल यूज आफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस -रोल ऑफ़ पब्लिक रिलेशन' विषय पर आयोजित व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आज खेती किसानी में भी एआई का उपयोग होने लगा है जिससे पेड़ पौधों के स्वभाव को समझने में आसानी हुई है। इसी तरह से मीडिया के क्षेत्र में भी खूब प्रचलन हो रहा है लेकिन हमें इतना ध्यान रखना होगा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पर ही काम करता है इसलिए हम जितनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ कंटेंट जारी करेंगे एआई भी उसी तरह से काम करेगा और सुखद परिणाम देगा। इससे पूर्व वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषण श्री गिरजा शंकर ने कहा कि एआई का उपयोग हम अपनी जरूरत के हिसाब से करें तो बेहतर होगा।

कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अर्चना कुमारी ने कहा कि हम एआई को अपने फेवर में भी कर सकते हैं इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सूझबूझ और समझदारी के साथ उपयोग करना होगा।

उन्होंने कहा कि हम अपने विवेक से काम करें ना कि एआई के गुलाम बनें। खबरों में उपयोग के दौरान डेटा वायस न हो एक तरफा कंटेंट न बने, इस बात का हम पूरा-पूरा ध्यान रखें। कार्यक्रम में विशेष अतिथि टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप मुंबई की संपादक श्रीमती रेखा खान ने एआई के उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी। पीआरएसआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एसपी सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने स्वागत वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में युवा पत्रकार व पीआरएसआई के कोषाध्यक्ष श्री केके शुक्ला की किताब 'डिजिटल जर्नलिज्म' का विमोचन हुआ। कार्यकम संचालन महेश सोनी ने किया।

पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ़ इंडिया भोपाल चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 24 महिलाओं को अचला/उदिता सम्मान प्रदान किया गया तथा जनसंपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अपर संचालक जनसंपर्क संजय जैन को लोक संपर्क सम्मान से अलंकृत किया गया। अंत में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुल सचिव अविनाश बाजपेई ने आभार व्यक्त किया।

जेल में कड़े पहरे में करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल और साथी

- आपस में नहीं कर सकते बात, कैदी रखते हैं नजर, हर 12 घंटे में जाती है रिपोर्ट

भोपाल (नप्र)। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आरटीओ के पूर्व करोड़पति कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को भोपाल की सेंट्रल जेल में ढाई महीने बीत गए हैं। 4 फरवरी को तीनों को पहली बार जेल भेजा गया था। 11 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सात दिन की रिमांड पर लिया और 17 फरवरी को वे दोबारा जेल पहुंचे। इस तरह तीनों ने ज्यूडिशियल कस्टडी में अब तक 75 दिन बिता लिए हैं। न उन्हें आपस में बातचीत करने की इजाजत है और न साथ रहने की। कुख्यात कैदियों की तरह तीनों की निगरानी को खोल दिया गया है। जेल की भाषा में निगरानी खोले जाने का मतलब राउंड अ क्लॉक नजर रखना होता है। तीनों के साथ दो-दो कैदी साय की तरह रहते हैं। यह कैदी जेल प्रशासन के विश्वसनीय हैं। यह कैदी हर 12 घंटे में अधिकारियों तक तीनों की हर गतिविधि की सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन होने वाली गणना में तीनों से चक्कर अधिकारी सीधी बातचीत करते हैं। इसमें तीनों जेल में बीत रहे हर लम्हे की जानकारी अधिकारियों को देते हैं। इसी के साथ अपने सेहत, अन्य कैदियों द्वारा किए जाने वाला व्यौहार की जानकारी भी उन्हें देते हैं। जेल में शरद को ब्लड प्रेशर और स्किन संबंधी बीमारियां लगातार बनी हुई हैं।

एक बार मिली आपस में बातचीत की इजाजत- सौरभ की ओर से लगातार उसके साथी शरद और चेतन से बातचीत करने की अनुमति मांगी जा रही है। 5 बार प्रयास के बाद जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक बार आपस में बातचीत करने की इजाजत दी गई। जेलर के कमरे में तीनों को साथ बैठाया गया। यहां करीब एक घंटे तक तीनों ने आपस में बातचीत की।

बिल्डिंग सेंटर में अलग-अलग बंद हैं- तीनों आरोपियों को ब खंड के करीब बिल्डिंग सेंटर नाम की जगह पर रखा गया है। यहां तीनों अलग-अलग बैरक में और कैदियों सहित जेल स्टॉफ की निगरानी में रहते हैं। जेल जाने के बाद से ही तीनों अन्य कैदियों से कम बातचीत करते हैं। सुबह समय पर नाश्ता लेते हैं। दोपहर का खाना भी पूरा खाते हैं। लेकिन रात के खाने को सौरभ और शरद न के बराबर ही खाते हैं। हालांकि चेतन तीनों समय जेल से मिले खाने को अच्छे से ही खाता है। हालांकि जेल की गर्मी ने तीनों को बेहाल कर रखा है।

नहीं दी गई लाइब्रेरी जाने की सुविधा- जेल में सौरभ, शरद और चेतन को ब खंड के पास बनी चार विशेष बैरक में से तीन में रखा गया है। इन बैरक में तीनों के अलावा 29-29 अन्य कैदी रह रहे हैं। इन कैदियों के बीच जेल प्रशासन के लिए अंदरखाने की खबरें जुटाने का काम करने वाले कैदी भी मौजूद हैं। जो पल-पल की अपडेट प्रहरियों के माध्यम से जेल प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तीनों की सुरक्षा को देखते हुए बैरक में आक्रामक कैदियों के साथ नहीं रखा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु अर्जन देव के प्रकाश पर्व पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिख धर्म के पांचवें गुरु, संत शिरोमणि गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी का संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग और मानव कल्याण का प्रतीक है। उनके विचार सर्वदा हम सभी को सत्य, सहिष्णुता और धर्मनिष्ठा के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहेंगे।

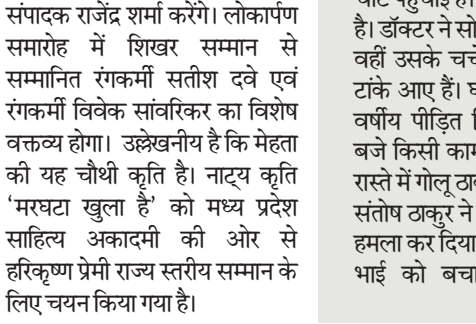

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलचीपुर के विधायक श्री हजारी लाल दांगी के पोते श्री अजय दांगी के विवाह समारोह में शामिल होकर आशीर्वाद दिया।

रतलाम समेत प्रदेश के 5 जिलों में चलेगी लू

ग्वालियर-शिवपुरी में रातें भी गर्म रहेंगी, भोपाल, इंदौर-उज्जैन में भी तेज गर्मी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के 5 जिले रविवार को हीट वेव यानी, लू की चपेट में थे। मौसम विभाग ने रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं, ग्वालियर, शिवपुरी और मंडला की रात गर्म रह सकती है। इससे पहले शनिवार को भी कई जिलों में लू चली थी। इधर, दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। शिवपुरी सबसे गर्म रहा। यहां टेम्परेचर 44 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, कुल 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा।

इन शहरों में पारा 40 डिग्री के पार- मौसम विभाग के अनुसार, सागर-नर्मदापुरम में 42.8 डिग्री, मंडला-खजुराहो में 42.6 डिग्री, नौगांव में 42.5 डिग्री, दमोह में 42.4 डिग्री, उमरिया में 42.3 डिग्री, टीकमगढ़ में 42 डिग्री, रायसेन में 41.8 डिग्री, खरगोन में 41.6 डिग्री, खंडवा में 41.5 डिग्री, रतलाम में 41.4 डिग्री, शाजापुर में 41.3 डिग्री, धार, मलाजखंड में 41.1 डिग्री, सिवनी में 40.6 डिग्री, बैतूल में 40.5 डिग्री, सतना में 40.3 डिग्री, छिंदवाड़ा में 40.2 डिग्री और नरसिंहपुर में पारा 40 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 41.4 डिग्री, इंदौर में 40.2 डिग्री, ग्वालियर में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 40.5 डिग्री और जबलपुर में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

फिलहाल पारे में बढ़ोतरी का दौर- मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि अगले कुछ दिन तक पारे में बढ़ोतरी का दौर रहेगा। इस दौरान लू का अलर्ट भी जारी किया गया है।

ऐसा रहेगा अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा- तीसरा सप्ताह- उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 2 से 3 दिन लू चल सकती है। हल्की बारिश होने की संभावना है।

चौथा सप्ताह - उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लगातार जोर पकड़ने के साथ न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक यानि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन के साथ रातें भी गर्म हो जाएंगी। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में पारा 43-45 डिग्री जबकि इंदौर, उज्जैन-भोपाल सहित बाकी प्रदेश में 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। बंगाल क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अप्रैल के आखिरी में 3 से 4 दिन तक लू का असर रह सकता है।

तालाब में डूबने से युवक और किशोर की मौत

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी के चमरऊआ गांव में रविवार दोपहर तालाब में नहाने गए एक युवक और एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। ये हादसा दोपहर करीब ढाई बजे के आसपास खनियाधाना थाना क्षेत्र में हुई।

जानकारी के अनुसार, चमरऊआ गांव निवासी करण केवट(18) पिता रघुवर केवट और अभिषेक केवट(13) पिता विक्रम केवट गांव के कुछ अन्य युवकों के साथ नहाने के लिए तालाब गए थे। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे वे डूबने लगे। मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने उन्हें तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

दोनों को तैरना नहीं आता था- दोनों को तत्काल खनियाधाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि दोनों को तैरना नहीं आता था। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव- घटना की सूचना मिलते ही खनियाधाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीसीसी चीफ जीतू बोले -

महाधिवक्ता ने कोर्ट में उलझाया ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण

भोपाल (नप्र)। मप्र में कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किए गए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मुद्दे की आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेन्द्र कुशवाहा और सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर के साथ कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

कमलनाथ सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया, भाजपा ने रोका- पटवारी ने कहा- हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने ओबीसी आरक्षण 14प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। मार्च 2019 में 27प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर आए। फिर भाजपा, आरएसएस और भाजपा समर्थित आरक्षण विरोधी लोगों ने इसको रोकने के लिए एक एमबीबीएस की छात्रा (जो पीजी कर रही थी) से कोर्ट में पिटीशन लगवाई और अध्यादेश पर रोक लगवा दी। कमलनाथ सरकार ही दो महीने बाद कानून लेकर आई कि ओबीसी आरक्षण 27प्रतिशत होना चाहिए। यानि कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए विधायिका से 27प्रतिशत आरक्षण लागू कराया, लेकिन जब कार्यपालिका को उस कानून का पालन कराना था उसी दौरान हमारी सरकार चली गई। उसके बाद ओबीसी को 27प्रतिशत आरक्षण के सारे विरोधी एकजुट हो गए।

कोर्ट का बहाना बनाकर क्रियान्वयन नहीं कर रही भाजपा सरकार- जीतू पटवारी ने कहा- मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रति. आरक्षण देने की बजाय सरकार लगातार उन्हें धोखा दे रही है। भाजपा सरकार ने कोर्ट का बहाना बनाकर इस कानून पर अमल नहीं किया। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कुछ नौकरियों में तो 27 प्रति. आरक्षण दिया, लेकिन कई भर्ती प्रक्रियाओं में फिर से 14 प्रति. ही लागू किया। यानि 'जब चुनाव आता है, तब भाजपा सरकार आरक्षण लागू कर देती है और बाद में उसे रोक देती है। यह सिर्फ दिखावा है।'

महाधिवक्ता ने सरकार के इशारे पर ओबीसी आरक्षण को उलझाया- पटवारी ने मप्र के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार के इशारे पर कोर्ट में मामले को उलझाया और करोड़ों रुपए फीस लेकर ओबीसी वर्ग के हक को रोका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं है, तब भी सरकार बहाना बनाकर मामले को टाल रही है।

पटवारी ने कहा मप्र के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को नर्सिंग घोटाले के मामले में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। प्रशांत सिंह के खिलाफ हम लोकायुक्त में शिकायत करेंगे। भाजपा सरकार ने कार्यपालिका और विधायिका के पास अधिकार होते हुए भी 27प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं किया, जिससे संविधान की मूल भावना और न्यायपालिका के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है।

मध्य प्रदेश में मई से हो सकते हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में नौ वर्ष से बंद पदोन्नतियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारियों से परामर्श के बाद पदोन्नति नीति का प्रारूप तैयार किया है। इसे कैबिनेट में अंतिम रूप दिया जाएगा। मई में यह नीति कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया विभागों में प्रारंभ हो जाएगी। जिन विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या कम है, वहां पदोन्नति पहले हो सकती है। मंत्रालयीन कर्मचारियों को भी पहले झटके में ही पदोन्नति मिल सकती है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तैयारी भी है।

मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति- सूत्रों के अनुसार मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अप्रैल 2016 से पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट से रोक है। इन नौ वर्षों में लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

विभागीय भर्ती नियमों में बदलाव नहीं- फरवरी 2025 में विधि विभाग ने अपने यहां के लगभग डेढ़ सौ कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया। इसका आधार यह था कि आरक्षण नियम रद होने के बाद भी विभागीय भर्ती नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इन नियमों के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है।

पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए कहा था

विधि विभाग में पदोन्नति को आधार बनाकर कर्मचारी संगठनों ने शासन से सभी कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति की मांग की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) और विधि विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए कहा था। सूत्रों के अनुसार जीएडी ने इसकी तैयारी कर ली है।

आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा

कुछ विभागों नें कोर्ट के निर्णय के अधीन रखते हुए कर्मचारियों-अधिकारियों को पदोन्नत कर कार्यवाहक पद तो दे दिया है, पर उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण डीपीसी कर उन्हें भी स्थायी तौर पर पदोन्नत किया जाएगा ताकि उस पद के अनुरूप लाभ मिले।

सागर से हिंदू युवती को भगाकर ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

मुस्लिम युवक ग्वालियर स्टेशन पर पकड़ा गया, लड़की भी साथ मिली

- युवती की बारात से एक दिन पहले ही उसे भाग ले गया था युवक
- सनौधा गांव में फैल गया था तनाव, आरोपी की दुकान भी जलाई

सागर (नप्र)। सानौधा से भागे युवक- युवती को ग्वालियर पुलिस ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया है। बीते रोज हिंदू लड़की और मुस्लिम समाज का लड़का भागा था। लड़की की एक दिन बाद बारात आने वाली थी, इसी बीच मुस्लिम समाज के लड़के के साथ भागने से गांव में तनाव का माहौल था। इसको लेकर तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाएं भी हुईं। इसके बाद यहां पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक सागर एसपी विकास शाहवाल को लड़का-लड़की के ग्वालियर भागने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर एसएसपी से मदद मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट थी।

जैसे ही ट्रेन से उतरे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया- दोनों शनिवार रात जैसे ही ट्रेन से उतरे पड़ाव थाना पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। प्रेमी जोड़ा पकड़े जाने की सूचना सागर पुलिस को दे दी है। पड़ाव थाना प्रभारी आलोम परिहार ने बताया कि पुलिस कप्तान को सूचना मिली थी कि सागर से भागे युवक-युवती भोपाल के रास्ते ट्रेन से ग्वालियर आने वाले हैं। इसका पता चलते ही पुलिस की एक टीम स्टेशन पर तैनात कर दी गई। जैसे ही युवक-युवती यहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें निगरानी में ले लिया। पुलिस ने दोनों की जानकारी सागर पुलिस को दी है। सागर पुलिस ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है।

सानौधा में अब शांति का माहौल, आरोपित पर कार्रवाई की मांग- वहीं सानौधा गांव में अब शांति का माहौल है, लेकिन लोग लड़की को भगाने वाले आरोपित अनश पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लड़की की एक दिन बाद बारात आना था। आरोपित ने लव जिहाद के तहत लड़की को फंसाया। गांववालों के मुताबिक इस तरह की उनके गांव में यह पांचवीं घटना है। आरोपित प्राचीन किले की जमीन पर अतिक्रमण किए हैं। परिवार के लोग अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उन पर कार्रवाई होना चाहिए।

जनकल्याण और सुशासन में दें योगदान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने मैदानी अधिकारियों को दिए निर्देश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनकल्याण के लिए अधिकारी मैदान में उतरें। नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर, सुशासन की दिशा में अपना प्रभावी योगदान दें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के कलेक्टर्स-कमिश्नर्स, एसपी, आईजी से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी जिलों में उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसानों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखें। पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद रहे। आमजन से अधिकारी-कर्मचारी का व्यवहार विनम्र और अच्छा हो। कार्यालयों में आने वाले नागरिक को समाधान प्राप्त हो। पराली नियंत्रण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। किसानों को सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे उपकरण अधिक संख्या में उपलब्ध करवाए जाएं। इससे किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय भी बचेगा। ग्रीष्मकाल में स्वास्थ्य का ध्यान रखें नागरिक- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिकों को ग्रीष्मकाल में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए।

संजय मेहता की नाट्य कृति 'संत तुकाराम' का लोकार्पण 23 को

भोपाल। वरिष्ठ रंग निर्देशक संजय मेहता की नवीन नाट्य कृति 'संत तुकाराम' का लोकार्पण 23 अप्रैल को गांधी भवन के मोहनिया सभागृह में होगा। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. विकास दवे होंगे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वदेश ज्योति के संपादक राजेंद्र शर्मा करेंगे। लोकार्पण समारोह में शिखर सम्मान से सम्मानित रंगकर्मी सतीश दवे एवं रंगकर्मी विवेक सांवरिकर का विशेष वक्तव्य होगा। उल्लेखनीय है कि मेहता की यह चौथी कृति है। नाट्य कृति 'मरघटा खुला है' को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की ओर से हरिकृष्ण प्रेमी राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयन किया गया है।

बीना में सांसद प्रतिनिधि ने नाबालिग भाई-बहन को पीटा

लाठी-रॉड से हमला, लड़की को गंभीर चोट, भाई के सिर में 5 टांके

बीना (नप्र)। बीना में सागर की बीजेपी सांसद लता वानखेड़े के प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच संतोष ठाकुर और उसके समर्थकों ने दो नाबालिग भाई-बहन से जमकर मारपीट की। पीड़ित भाई-बहन को गंभीर हालत में सागर रेफर किया गया है। बच्ची के चाचा का कहना है कि आरोपियों ने भतीजी के पेट और प्राइवेट पार्ट में भी चोट पहुंचाई है। नाक से खून निकल रहा है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी के लिए कहा है। वहीं उसके चचेरे भाई के सिर में पांच टांके आए हैं। घटना नौगांव की है। 17 वर्षीय पीड़ित किशोर शनिवार रात 9 बजे किसी काम से दुकान जा रहा था। रास्ते में गोलू ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर और संतोष ठाकुर ने डंडे और रॉड से उस पर हमला कर दिया। 16 वर्षीय बहन अपने भाई को बचाने पहुंची, तो सांसद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर ने उस पर भी हमला किया। संतोष के भतीजे किट्टू ठाकुर और भोला ठाकुर भी वहां आ गए। सभी ने मिलकर दोनों नाबालिगों को बेहोश होने तक पीटा।

12 से ज्यादा लोगों ने हमला किया- परिजन ने घायल बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां से दोनों को सागर रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावर 12 से ज्यादा थे। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर सांसद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर, गोलू ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर, किट्टू ठाकुर और भोला ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नाबालिग बोला- गाली देने से मना किया तो रॉड मारी- पीड़ित किशोर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है- मैं शनिवार रात दुकान सामान लेने जा रहा था। तभी घर के सामने रोड पर गांव के गोलू ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर, संतोष ठाकुर हाथ में डंडा और रॉड लिए मिले। किसी पुरानी बात पर मुझे गंदी-गंदी गालियां देने लगे। पीड़ित के मुताबिक- मैंने गालियां देने से मना किया तो गोलू ठाकुर ने रॉड मारी। रॉड मेरे सिर में लगी और खून निकलने लगा। हरि सिंह और संतोष ठाकुर डंडे से पीटने लगे। मेरे दाहिने हाथ के पंजे, गर्दन, बाएं हाथ की पिडंली पर चोट आई।

बीच-बचाव करने आई बहन को भी लात-घूंसों से पीटा- शोर सुनकर पीड़ित के ताऊ की नाबालिग बेटी बीच-बचाव करने लगी। इस पर संतोष के भतीजे किट्टू ठाकुर, भोला ठाकुर आ गए और दोनों बहन को लात-घूंसों से और संतोष डंडे से मारपीट करने लगा। जिससे उसे सिर दाहिने हाथ की उंगली, नाक में चोट आई। ये देखकर नाबालिग लड़के ने शोर मचाया, जिसे सुनकर माता-पिता भी वहां पहुंच गए। इनसे भी आरोपियों ने मारपीट की। परिवार के बाकी लोगों को भी मारपीट कर भगा दिया। वे जाते-जाते कह रहे थे कि आज तो बच गए दोबारा दिखे तो जान से खत्म कर देंगे।

पीड़ित परिवार ने सांसद को रोका- बीना से कुरवाई जा रही सांसद लता वानखेड़े को पीड़ित परिवार ने अपने गांव नौगांव के पास रोक लिया। पीड़ित परिवार ने उनके प्रतिनिधि द्वारा नाबालिग बच्चों के पिटाई के बारे में बताया। इसी बीच आरोपी संतोष भी बेधड़क सांसद के पास पहुंच गया और पीड़ित परिवार को देख लेने की बात कही। पीड़ित पक्ष ने आरोपी की बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार ने मिलकर मारपीट की है। मामले में सांसद लता वानखेड़े ने जांच कराने कहा है।

पांच महीने पहले शुरू हुआ विवाद- दोनों परिवारों में विवाद लगभग पांच माह पहले शुरू हुआ था। दरअसल, कुशवाहा परिवार के तीन एकड़ खेत में पानी की मोटर के लिए केबल डली थी। वह केबल अज्ञात लोगों ने काट दी। अशोक कुशवाहा ने बताया कि वह केबल संतोष के इशारे पर ही काटी गई थी। तभी से विवाद चल रहा है।

संपादकीय

नक्सलमुक्त गांव- बड़ी उपलब्धि

सरकारी दावे पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़ेसेट्टी राज्य का पहला नक्सलमुक्त गांव बन गया है। यह उपलब्धि गांव के 11 नक्सलियों के आत्म समर्पण के बाद हासिल हुई है। बडेसेट्टी गांव सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर और रायपुर से 430 किलोमीटर दूर है। इसके पीछे केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त नक्सलविरोधी अभियान है। सुकमा के एसपी (किरण चव्हाण के अनुसार पुलिस पिछले 15 दिनों से बडेसेट्टी पंचायत के प्रतिनिधियों के संपर्क में थी। पुलिस गांव के मिलिशिया और प्रतिबंधित संगठन की क्रांतिकारी पार्टी समिति के सदस्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के बाकी जिले भी जल्द ही नक्सलमुक्त होकर विकास की मुख्य धारा में लौटेंगे। क्योंकि 'बंदूक की नली से ही क्रांति निकलती है' जैसे अव्यवहारिक और अभारतीय विचारों की राह पर चलकर नक्सलियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उल्टे इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में शोषण, दमन और अत्याचार की नई कहानियां जरूर लिखी गईं। वैसे भी नक्सलवाद अतिवादी वामपंथी सोच की पैदाइश है, जिससे समझदारी वामपंथियों ने भी किनारा कर लिया था। यही कारण है कि जिस पश्चिम बंगाल में जमींदारी प्रथा के खिलाफ नक्सलवाद ने जन्म लिया था, वहां तो जल्द ही दम तोड़ गया, लेकिन नक्सलियों और उनके आकाओं ने प.बंगाल से बाहर छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यो के घने जंगलों वाले इलाकों में पैर जमा लिए। ये नक्सली उन भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने में कामयाब रहे जो पहले ही शोषण, भेदभाव और गरीबी का शिकार थे। नक्सलियों के वैचारिक और आर्थिक पोषण का काम शहरी नक्सली करते रहे, जो अब कम रह गए हैं और सरकारी एजेंसियों के दबाव के कारण छिपते फिर रहे हैं। हालांकि इन नक्सलियों ने पिछले कुछ सालों से खुद को माओवादी कहना शुरू कर दिया था। वे उस माओवाद को जिंदा रखना चाहते थे, जिसका अब चीन में भी कोई नामलेवा नहीं है। बहरहाल बड़ेसेट्टी गांव में विकास और शांति की नई धारा बह सकती है। सरकार की नीति के अनुसार गांव को उसकी विकास परियोजनाोंके लिए एक करोड़ रू. मिलेंगे। इसकी घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले दंतेवाड़ा के दौरे पर छत्तीसगढ़ सरकार की इस घोषणा की सराहना की थी कि जो गांव खुद को 'नक्सल-मुक्त' घोषित करेगा और माओवादियों का आत्मसमर्पण कराएगा, उसे 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शाह ने गांव में बैठकें करने, चरमपंथियों तक पहुंचने और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने का आग्रह किया था। इसी रणनीति का पालन बडेसेट्टी में किया गया और गांव अब नक्सल मुक्त हो गया है। दरअसल नक्सलवाद के रूप में हिंसक आंदोलन की कमर तोड़ने का मुख्य श्रेय अमित शाह को ही जाता है, जिन्होंने केन्द्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय बिठाकर नक्सलियों को बेदम कर दिया। सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार और संसाधन दिए गए तथा घने जंगलों में घुसने की इजाजत दी गई। इस फ्री हैंड का नजीता यह हुआ है कि देश में नक्सलवाद केवल चार जिलों तक सिमट गया है। वो नक्सलवाद जो कभी देश में उत्तर से दक्षिण तक 'रेड कॉरिडोर' बनाने का दावा करता था। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को 31 मार्च 2026 तक आखिरी नक्सली को भी खत्म करने की डेड लाइन दी हुई है। नक्सलवाद का यह खात्मा दो स्तरों पर हो रहा है, पहला तो नक्सलियों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई और दूसरे उनका समर्पण करवाना। सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी अच्छी नीति लागू की है। उसका भी असर इस अभियान में देखने को मिल रहा है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

शिक्षा सरकारी हो बाजारी नहीं

केंद्र की भाजपा सरकार ने शिक्षा नीति के दस्तावेज तैयार करने के लिये इसरो के वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन कमेटी का गठन किया था और नई शिक्षा नीति का दस्तावेज उनके द्वारा लागू किया है। हालांकि उन्होंने भाषा के सवाल को लेकर दो महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। एक तो यह कि छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर दिया जाये। दूसरा, हिंदी को मातृभाषा का स्थान मिले, परंतु इस समिति की रपट आने और केंद्र सरकार के कुछ कदम बढ़ाने के बाद जब राष्ट्रभाषा के सवाल पर तमिलनाडु की सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया तब पहले ही भारत सरकार पीछे हट गयी। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हिंदी को बलात लागू करना चाहिये परंतु जब सरकारें उसकी मातृ संस्था से हिंदी-हिंदी का गीत गाती हैं तो इनका नैतिक दायित्व होता है कि अपनी ही कमेटी को लागू कराये या कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कस्तूरी रंजन को संवाद का दायित्व सौंपते। देश की सभी सूबे की सरकारों के मुख्यमंत्रियों की सामूहिक बैठक आयोजित करते, कोई सामूहिक हल निकाल सकते, इसकी पहल करते।

भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के दस्तावेज को लगभग 4 वर्ष होने को आए है। इसे बावजूद भी इसे अभी भी नई शिक्षा नीति कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों, बल्कि कुछ दशकों में जो केंद्र सरकारें आई हैं उन्होंने शिक्षा नीति में अपनी राजनैतिक जरूरत के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव किए हैं। चूंकि यह सरकारी दस्तावेज है, इनके बनाने वाले बुद्धिजीवी आमतौर पर सरकार के अनुकूल होते हैं। दस्तावेज बनाने वाली कमेटी को सरकार ही नामजद करती है और यही सरकारें इन कमेटियों की रपट आने के बाद उसे पूर्णतरू या आंशिक लागू करने की घोषणा करती है। परंतु यह एक सुविदित तथ्य है कि कमेटियां रपट देने के पहले सरकार से मसिवरा करती हैं और उनकी सोच, दिशा-दशा को अपनी रपट में या सिफारिशों में समाहित करती हैं।

केंद्र की भाजपा सरकार ने शिक्षा नीति के दस्तावेज तैयार करने के लिये इसरो के वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन कमेटी का गठन किया था और नई शिक्षा नीति का दस्तावेज उनके द्वारा लागू किया है। हालांकि उन्होंने भाषा के सवाल को लेकर दो महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। एक तो यह कि छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर दिया जाये। दूसरा, हिंदी को मातृभाषा का स्थान मिले, परंतु इस समिति की रपट आने और केंद्र सरकार के कुछ कदम बढ़ाने के बाद जब राष्ट्रभाषा के सवाल पर तमिलनाडु की सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया तब पहले ही भारत सरकार पीछे हट गयी। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हिंदी को बलात लागू करना चाहिये परंतु जब सरकारें उसकी मातृ संस्था से हिंदी-हिंदी का गीत गाती हैं तो इनका नैतिक दायित्व होता है कि अपनी ही कमेटी को लागू कराये या कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कस्तूरी रंजन को संवाद का दायित्व सौंपते। देश की सभी सूबे की सरकारों के मुख्यमंत्रियों की सामूहिक बैठक आयोजित करते, कोई सामूहिक हल निकाल सकते, इसकी पहल करते।

वैसे भी सरकार को यह चाहिये था कि रपट को स्वीकार करने से पहले सभी राज्यों की सरकारों से बातचीत करते। और उसके बाद ही घोषणा करते। वैसे भी भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक फेडरल रिपब्लिक है जिसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता की भी एक संवैधानिक सीमा तक अधिकार दिये गये हैं। अगर इतना भी सरकार करती कि तमिलनाडु सरकार को कम से कम हिंदी को केंद्र से संपर्क की भाषा के रूप में स्वीकार कराने की घोषणा करती तो कुछ मामला आगे बढ़ता। अगर भारत सरकार ने यूपीएससी में सी सेट को हटा दिया होता (जिसमें फिर से अंग्रेजी की अनिवार्यता लागू कर दी।) तो भी कुछ रास्ता निकलता परंतु जब केंद्र सरकार राष्ट्रभाषा के सवाल पर स्वतरू अपराधी है तो वह राज्यों से कहने का नैतिक अधिकार खो देती है। अगर अभी भी सरकार यह निर्णय करे कि जिस राज्य के कैडर के लिये किसी व्यक्ति का चयन होता है उसे उस राज्य की प्रादेशिक भाषा सीखना अनिवार्य होगा और अगर उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग दक्षिण भारत के राज्यों के लिये चयनित होते हैं तो वे संबंधित राज्य की भाषा को सीखेंगे तो फिर दक्षिण भारत के अधिकारियों को भी हिंदी या राष्ट्रभाषा सीखने के लिये कहना तार्किक होता।

नई शिक्षा नीति के देश पर क्या प्रभाव पड़े हैं इसका आंकलन कुछ घटनाओं से हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई वर्ष 2023-24 की रपट सरकार के तमाम दावों की पोल खोल देती है जिसमें बताया गया है कि देश में बिना छात्र वाले स्कूलों की संख्या लगभग 13 हजार हो गयी है जबकि इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की संख्या 26 हजार से बढ़कर 31981 हो गई है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बगैर छात्रों वाले स्कूलों में लगभग 32 हजार शिक्षक नियुक्त किये हैं जिन पर औसतन सालाना 2 हजार करोड़ हो रहे हैं?

वहीं दूसरी तरफ देश में 110271 स्कूल ऐसे भी हैं जहां मात्र एक ही शिक्षक है और वहां छात्रों की क्या पढ़ाई होती होगी यह अकल्पनीय है। अगर सरकार नई शिक्षा नीति के बाद स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाई तो शिक्षा व्यवस्था की हालत समझी जा सकती है।

अभी भारत सरकार ने सनातन ज्ञान परंपरा के ऊपर काफी जोर दिया है और इसके माध्यम से स्कूलों से लेकर विवि तक सनातन ज्ञान परंपरा के पढ़ाने के नाम पर शिक्षक या व्याख्याता भेजे जा रहे हैं। यह सनातन ज्ञान परंपरा कहीं न कहीं धार्मिक परंपराओं से जुड़ी है और यह एक प्रकार से अघोषित धार्मिक शिक्षण भी है। बुद्ध धर्म भारतीय धर्म है और जिसकी ज्ञान परंपरा हिंदू ज्ञान परंपरा से कुछ पृथक है। इसी प्रकार जैन धर्म भी भारतीय है और उसकी ज्ञान परंपरा कुछ पृथक है। क्या इन धर्मों की ज्ञान परंपरा को सनातन ज्ञान परंपरा में शामिल किया गया है? मेरी जहां तक जानकारी है कि शिक्षण संस्थाओं में सनातन ज्ञान के नाम पर हिंदू धर्म की ज्ञान परंपराओं को पढ़ाया जा रहा है। वैसे भी धार्मिक संस्थान सरकार के द्वारा आयोजित करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अच्छा हो कि हिंदू धर्म के संस्थान अपनी ज्ञान परंपरा को धार्मिक संस्था के माध्यम से पढ़ायें वरना देर सवेर देश में यह भी विवाद का एक कारण बनेगा। फिर इतिहास जिसे अंग्रेजों ने विकृत किया उसे सुधारने के नाम पर बदला जा रहा है और अतीत की त्रुटियों को स्वीकार कर सुधारने की बजाय उन्हें इतिहास के पन्नों से हटाया जा रहा है। अंग्रेजों ने इतिहास की गलत ढंग से व्याख्या कर उसे विकृत किया था, अब आज की सरकार इतिहास के तथ्यों को हटाकर या छिपाकर इतिहास के पन्नों को फाड़ रही है।

वि.वि. जो उच्च शिक्षा के केंद्र रहे हैं उन्हें सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर बाजार के संस्थान बना रही है। अब भारत सरकार वि.वि. अनुदान आयोग वि.वि. के निर्माण के लिये अनुदान की बजाय कर्ज दे रहा है जिसे उन्हें एक समय अवधि तक ब्याज सहित चुकाना होगा। स्वाभाविक है कि अभी विवि में जो कुलपति या शिक्षक हैं वे केलव शिक्षण या शोध का काम करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि उनमें कुछ कमियाँ हैं (शोध के नाम या नौकरियों के नाम पर) शिक्षक व अन्य विवि के अधिकारी वांछित परिणाम नहीं दे पा रहे। इसमें उनकी पदलिप्सा और धनलिप्सा बड़ा कारण है। शायद इसलिये वे अपवाद छोड़कर रीढ़ विहीन जैसे हो गय हैं जो सरकारों के या तंत्र के सामने घुटने टेकना तो दूर दंडवत हो गये हैं। जब मैं यह देखता या सुनता हूँ कि केंद्रीय विवि के कुलपति (कुलगुरु) जब शिक्षा मंत्रालय के सचिव की कुर्सी के सामने घंटों बैठे रहते हैं, उससे आदेश लेते हैं, उनकी अनुनय विनय करते हैं तो शिक्षा जगत का कितना पतन हुआ है, इसका ये प्रमाण है। उस दौर की याद आती है जब शिक्षा मंत्री तो दूर प्रधानमंत्री भी विवि के कुलपति को बुलाने का साहस नहीं करता था। परंतु पैसे के नाम पर और भ्रष्टाचार से बने कुलगुर अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। एक तरफ सरकार सनातन ज्ञान परंपरा का प्रचार करती है, पर वह यह भूल जाती है कि भारत के अतीत में शिक्षक का दर्जा राजा से भी बड़ा होता था। कई बार ऐसा लगता है कि यह सरकार सनातन ज्ञान परंपरा के नाम पर जो अच्छी परंपरायें थीं उन्हें छोड़कर केवल अन्य प्रकार की परंपराओं को ज्ञान परंपराओं के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

यूजीसी की सिफारिश में अभी हाल ही में केंद्र और शिक्षामंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मसौदा तैयार किया है। 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव की योग्यता को हटाया जा रहा है तथा उद्योग जगत और कारपोरेट जगत के बगैर शिक्षा के अनुभव के कुलपति भी नियुक्ति किये जा सकते हैं। या कुलपति का पद अब शैक्षणिक पद नहीं बल्कि व्यापारिक पद हो जायेगा। और यह सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर शिक्षण संस्थानों को शिक्षा का बाजार बनाने के लिये कर रही है। क्योंकि सरकार भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की कल्पना के अनुसार शिक्षा देने के अपने दायित्वों से हट रही है। यह एक प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा के संपूर्ण निजीकरण की शुरुआत है। निजी विवि तो पहले भी थे, परंतु अब सरकारी विवि को भी निजी जैसा ही बना दिया जायेगा। यह आरएसएस के समान कुलगुरुओं में लेटरल एंट्री है। नाम सरकारी होगा, काम बाजारू होगा। शायद इस सरकार के लिये नई शिक्षा नीति के माध्यम से खुले बाजार के हाथ सौंपना है।

यह घटना अकेले शिक्षा की बर्बादी को ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के विकास के दावों की भी पोल खोलती है। जहां बजट की राशि और टैक्स की दरें आमजन के लिये बढ़ रही है और दूसरी तरफ शिक्षा को बाजार का उत्पाद बनाया जा रहा है। अब यह देश के जनमत पर निर्भर है कि क्या वह अपने देश की शिक्षा को सरकारी चाहता है या बाजारी।

जलवायु संकट

डॉ. रामानुज पाठक

हरित ऊर्जा में निवेश- विज्ञान-सम्मत आर्थिक विकास की राह

आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की घटती उपलब्धता से जूझ रही है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से बाहर निकलकर नवीन, हरित और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाएँ। हरित ऊर्जा, जो न केवल स्वच्छ और नवीकरणीय होती है, बल्कि यह हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी संतुलित करती है, अब भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक पूंजी के रूप में उभर रही है। हरित ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, जैव ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा जैसे विकल्प आते हैं जो जीवनदायिनी संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इनका उत्पादन न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि यह विकासशील और विकसित देशों के लिए आर्थिक अवसरों का एक नया दायरा खोलता है। यह संसाधन किसी विशेष स्थान, सीमित भंडार या बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इन्हें आसानी से स्थानीय स्तर पर उत्पन्न किया जा सकता है।

हरित ऊर्जा में निवेश न केवल ऊर्जा संकट का समाधान प्रदान करता है, बल्कि यह रोजगार सृजन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, और सामाजिक समृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस आलेख का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कैसे हरित ऊर्जा में निवेश आर्थिक विकास की कुंजी हो सकता है, और क्यों यह निवेश न केवल पर्यावरणीय बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। साथ ही, आज नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों, निवेशकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए यह समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि हरित ऊर्जा में निवेश का क्या वास्तविक लाभ है, और इसे किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है।वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु संतुलन की कुंजी बन चुकी है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित हैं तथा इनके उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में हरित ऊर्जा (Green Energy) एक पर्यावरणीय, वैज्ञानिक और आर्थिक विकल्प के रूप में उभर रही है। इसमें सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास तथा भू-तापीय ऊर्जा जैसे स्रोत सम्मिलित हैं, जो पुनरुत्पाद्य और स्वच्छ हैं।

हरित ऊर्जा में निवेश न केवल जलवायु संकट के समाधान का माध्यम है, बल्कि यह एक ऐसा विज्ञान-सम्मत रास्ता है जिससे दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेश और ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है।

1. हरित ऊर्जा का वैज्ञानिक आधार

हरित ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है जो नियमित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। उदाहरणस्वरूप, सूर्य की ऊर्जा अनंत है और पृथ्वी पर हर दिन 173,000 टेरावॉट ऊर्जा पहुँचती है—जो वैश्विक ऊर्जा मांग से 10,000 गुना अधिक है। पवन ऊर्जा वायुमंडलीय तापमान और दबाव भिन्नताओं पर आधारित होती है, और जलविद्युत गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का अनुप्रयोग है। इन स्रोतों का वैज्ञानिक रूप से स्थायित्व, कम उत्सर्जन और स्थानीय उत्पादन की क्षमता, इन्हें भविष्य की ऊर्जा प्रणाली का आधार बनाती है।

2. आर्थिक संभावनाएँ-स्थिरता और समृद्धि का द्वार

हरित ऊर्जा में निवेश केवल पर्यावरणीय हित नहीं, बल्कि आर्थिक चमत्कार की संभावना भी प्रस्तुत करता है-

रोज़गार सृजन- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, हरित ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक लगभग 1.2 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं। सौर पैनल निर्माण, टरबाइन रखरखाव, ऊर्जा निरीक्षण और प्रौद्योगिकी शोध जैसे क्षेत्रों में विशाल अवसर हैं।

स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन- हरित ऊर्जा तकनीकों की मांग से क्षेत्रीय स्तर पर विनिर्माण, सेवा और प्रशिक्षण केंद्र विकसित हो सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को बल मिलेगा।

ऊर्जा की लागत में गिरावट- पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा की लागत में लगभग 85 प्रति. और पवन ऊर्जा की लागत में 60 प्रति.तक की कमी आई है। यह दर्शाता है कि हरित ऊर्जा तकनीकी दृष्टि से भी परिपक्व और लाभकारी बन रही है।

3. सामाजिक समावेश और न्याय

हरित ऊर्जा केवल तकनीकी विकल्प नहीं, सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक सशक्त माध्यम है-

ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण- भारत के दूरस्थ गाँवों में अब माइक्रो-ग्रिड और सौर स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएँ चल रही हैं। इससे न केवल ऊर्जा की पहुँच बढ़ी है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू उद्योगों को नई गति मिली है।

महिला सहभागिता- हरित ऊर्जा के उपकरणों की मरम्मत और संचालन का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। 'सौर सहेली' जैसे अभियान इस दिशा में नई सामाजिक संरचना की नींव रख रहे हैं।

स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता- पारंपरिक बायोमास जैसे लकड़ी या गोबर से खाना पकाने के दौरान उत्पन्न धुएँ से महिलाओं और बच्चों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। बायोगैस, एलईडी लाइटिंग और स्वच्छ ऊर्जा स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।

4. शिक्षा और जन-जागरूकता में भूमिका

हरित ऊर्जा के स्थायी विकास के लिए समाज का व्यापक जागरण आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार अनिवार्य है

विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम-अक्षय ऊर्जा पर केंद्रित पाठ्यक्रमों से छात्रों को नवाचार की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। एनआईटी, आईआईटी, और कई राज्य तकनीकी संस्थान इस दिशा में अनुसंधान परियोजनाएँ चला रहे हैं।

प्रयोगात्मक शिक्षण- सौर किट, लघु पवन टरबाइन मॉडल और ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं छात्रों में वैज्ञानिक रुचि और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं।

सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र- ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार-परक तकनीकी कौशल मिल रहे हैं, जिससे तकनीक केवल आयात न होकर स्थानीय स्तर पर अपनाई जा रही है।

5. नीति, निवेश और वैश्विक दिशा

हरित ऊर्जा के सतत विकास हेतु नीति समर्थन और वित्तीय व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हैं

नीतिगत पहल- भारत सरकार की 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन', 'सौर ऊर्जा मिशन', और 'उज्ज्वला योजना' जैसे कार्यक्रमों ने अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता बनाया है।

वित्तीय नवाचार- हरित बॉन्ड, क्रेडिट गारंटी योजना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल निवेश को सुगम बना रहे हैं। छोटे निवेशकों को भी अब हरित ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग- 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) जैसे मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका, इसे वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बनाती है।

6. भविष्य की दिशा- विज्ञान, नवाचार और संवेदनशीलता का समन्वय

आगामी वर्षों में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ हरित ऊर्जा को नई ऊँचाइयों तक ले जाएँगी

स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा संग्रहण-ऊर्जा भंडारण तकनीकों जैसे लिथियम-आयन बैटरी और पंपड हाइड्रो स्टोरेज, अक्षय ऊर्जा की अनियमितता की समस्या का समाधान कर रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण- ऊर्जा पूर्वानुमान, खपत विश्लेषण और स्मार्ट नियंत्रण प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दक्षता को बढ़ा रहा है।

हरित हाइड्रोजन- पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पन्न हरित हाइड्रोजन, भारी परिवहन, इस्पात उद्योग और ऊर्जा संचयन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है।

न्यायोचित संक्रमण- कोयले पर आधारित क्षेत्रों के श्रमिकों को हरित ऊर्जा कार्यों में पुनः प्रशिक्षित कर एक समावेशी संक्रमण संभव है। यह सामाजिक असमानता को कम कर सकता है।

निष्कर्ष

हरित ऊर्जा में निवेश महज एक पर्यावरणीय विकल्प नहीं, अपितु विज्ञान, समाज और अर्थव्यवस्था के समन्वय का प्रतीक है। यह जलवायु संकट का समाधान, रोजगार का स्रोत, और आत्मनिर्भरता की नींव है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने तकनीकी कौशल, नीति नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता के बल पर हरित ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी बने।

आज की आवश्यकता यह है कि हरित ऊर्जा को केवल सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन के रूप में स्वीकार किया जाए—जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग का सहयोग, और नागरिकों की भागीदारी से मिलकर एक हरित, समावेशी और प्रगतिशील भारत का निर्माण हो सके। आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की घटती उपलब्धता से जूझ रही है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से बाहर निकलकर नवीन, हरित और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाएँ। हरित ऊर्जा, जो न केवल स्वच्छ और नवीकरणीय होती है, बल्कि यह हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी संतुलित करती है, अब भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक पूंजी के रूप में उभर रही है।

हरित ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, जैव ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा जैसे विकल्प आते हैं जो जीवनदायिनी संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इनका उत्पादन न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि यह विकासशील और विकसित देशों के लिए आर्थिक अवसरों का एक नया दायरा खोलता है। यह संसाधन किसी विशेष स्थान, सीमित भंडार या बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इन्हें आसानी से स्थानीय स्तर पर उत्पन्न किया जा सकता है।

कटाक्ष

सुरेश रायकवार

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सिनेमा और साहित्य की एक बहस

दयारामजी शहर के जानेमाने साहित्यकार हैं जबकि उनका पोता सत्यम आधुनिक शिक्षा से शिक्षित और हिन्दी-अंग्रेज़ी सिनेमा का अति-अनुरागी युवक। देर रात सत्यम के घर में प्रवेश करते ही दयारामजी ने पूछा - कहाँ से आ रहे हो राजकुमार!

मूवी देखकर कभी-कभार थोड़ा साहित्य भी पढ़ लिया करो बेटा, क्या हर हफ्ते मूवी ही मूवी देखते रहते हो। नशा, अश्लीलता, मारधाड़, अपराध और फूहड़ संगीत के अतिरिक्त और क्या होता है आजकल इन मूवीज में! फिर सिनेमा का इतिहास तो अभी मात्र सौ-सवा सौ साल पुराना है जबकि साहित्य तो सनातन काल से लिखा जा रहा है। साहित्य सिनेमा से अधिक श्रेष्ठ है, साहित्य का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है।

साहित्य के महत्व को बताते हुए वे फिर बोले - बेटा सत्यम! साहित्य पढ़ने से विचारों की शुद्धि होगी, संस्कार सुधरेंगे। साहित्य से जहां बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है वहीं नए विचार और दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है, भाषा में सुधार के साथ-साथ जीवन के अलग-अलग पहलुओं को समझने और अनुभव करने में भी मदद मिलती है। दयारामजी ने कुल मिलाकर अपने पोते की क्लास ही लगा दी।सत्यम कुछ देर दादाजी की बातें सुनता रहा, फिर अचानक टीवी के बहसखोरों की तरह सिनेमा के पक्ष में अपने कुतर्क रखने लगा। अरे दादाजी अब देखो ना हमारे सिनेमा वाले कलाकार तो बड़े-बड़े सेलेब्रिटी हो जाते है। यहाँ तक कि एक सिनेमा का कलाकार तो यूक्रेन का राष्ट्पति तक बन गया, ये बात अलग है कि सिनेमा के हीरो की तरह वह देश की युद्ध समस्या को निपटाने में असफल रहा, फिर भी रूस के पसीने अवश्य छुड़वा दिये उसने।

हमारे देश में भी वर्तमान और भूतकाल के कई अभिनेता/अभिनेत्रियाँ भले ही राष्ट्पति या प्रधानमंत्री नहीं बन सके किन्तु राज्य के मुख्यमंत्री तो बन ही जाते है। सिनेमा कलाकारों का क्रेज भी इतना होता है कि यदि वे अपनी ही फिल्म देखने टॉकीज चले जाएँ तो लोग अपनी जान पर खेल कर उन्हे देखने जाते है। साहित्यकार को कौन जानता है? साहित्यकार बेचारा झोला लटकाए, आँखों पर मोटा चश्मा और सादे कपडों में रहने वाला एक निरीह और उपेक्षित प्राणी! अपनी रचना प्रकाशन अथवा पुस्तक प्रकाशित होने भर से ही अति प्रसन्न हो जाता है जबकि उसका स्वयं का परिवार तक उसकी खुशी में साथ नहीं देता। दिनभर सोश्यल मीडिया पर मेसेज भेज-भेज कर लोगों के बधाई संदेश की प्रतीक्षा करता रहता है।

सिनेमा की पहुँच आज टीवी के माध्यम से घर-घर में है, जबकि आपका ये साहित्य मध्यमवर्गीय और गरीबों द्वारा तो लगभग बिलकुल ही नहीं पढ़ा जाता है और अमीरों के यहाँ भी केवल उनके शो-केस की शोभा बढ़ाता दिखाई देता है। सिनेमा को हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, अमीर-गरीब सभी पसंद करते है किन्तु आपका साहित्य तो अधिकतर बूढ़े या कुछ जवान ही पढ़ते है। और फिर साहित्य को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए शिक्षित होना भी तो जरूरी है किन्तु सिनेमा के लिए यह भी जरूरी नहीं होता। सिनेमा एक अनपढ़ भी आसानी से समझ जाता है और सिनेमा में अभिनय करने वाले हीरो-हीरोइन को भी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती।

साहित्य में कवि, व्यंग्यकार, लेखक आदि की पहचान भी बहुत सीमित वर्ग तक होती है जबकि फिल्मों के कहानीकार, संगीतकार, नायक, नायिका यहाँ तक कि एक कोमेडियन की पहचान भी गली नुक्कड़ से लेकर देश-विदेश तक फैली होती है।

सिनेमा के लिए जगह-जगह टॉकीज बने है, साहित्य को पढ़ने के लिए आजकल कुछ लाइब्रेरी बची अवश्य हैं किन्तु वहाँ भी पुस्तकें धूल खा रही हैं, पढ़ने कोई नहीं जाता। आपके पिछले साहित्य-रत्न सम्मान के कार्यक्रम में गए थे जहां अन्य पुरुस्कार प्राप्त करने वाले और उनके हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त, समारोह हाल में नगण्य उपस्थिति थी जबकि सिनेमा में टिकट होने के बावजूद भीड़ बनी रहती है।

सिनेमा का समाज में सीधा और व्यापक प्रभाव पड़ता है, जबकि साहित्य का बहुत ही सीमित या कहें कुछ नहीं पड़ता। फिल्मे देखकर कितने ही बैंकों में डाका पड़ चुका है, फिल्मों से चोरी के नए-नए तरीके सीखे जाते है, अपराध की दुनिया में तो विशेष तौर पर चुनी हुई फिल्मे दिखाकर ट्रेनिंग दी जाती है। सास-बहू के लिए तो हर फिल्म में कोई ना कोई नुस्खा मिल ही जाता है। और प्यार करने वाले युवाओं के लिए तो कहना ही क्या! जिसे प्यार शब्द से नफरत हो उसे भी फिल्म देखकर प्यार हो जाए।

सिनेमा के कई हीरो-हीरोइन पर समान्यत: करोड़ों का तो आयकर ही बकाया रहता है, क्या आपने कभी साहित्य जगत में सुना है कोई करोड़पति साहित्यकार हुआ हो! सिनेमा वालों की आय जहां करोड़ों में होती है वहीं सरकार को भी मनोरंजन कर के माध्यम से आय होती है, जिससे देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। किन्तु आपके साहित्य से ना तो साहित्यकार को कुछ मिलता है ना ही सरकार को।

देश में फिल्मों से कहीं ज्यादा साहित्य लिखा जाता है किन्तु फिल्म निर्माण-क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, और इधर साहित्यिक पुस्तकें छापने वाली कई प्रिंटिंग प्रेस तक बंद हो चुकी हैं। अरे दादाजी! सिनेमा का टिकट हर कोई खरीद लेता है, साहित्य कौन खरीद रहा है, समाचार पत्र तक तो पड़ोसी से मांगकर पढ़ता है।पोते के तर्क-कुतर्क सुनते सुनते आखिरकार साहित्यकार दादाजी को नींद ही आ गई।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पर्यावरण

मनीष जैसल

लेखक-पशु पक्षी प्रेमी

बेज़ुबानों के लिए दिल में जगह रखिए

पशु और पक्षी न केवल जैव विविधता का हिस्सा हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अपरिहार्य हैं। गाय, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, हाथी, चिड़ियाँ, और कई अन्य प्रजातियाँ — हर एक का अपना महत्व है। जैसे मधुमक्खियाँ परागण के माध्यम से फसलों को बढ़ावा देती हैं, वैसे ही चिड़ियाँ और कीट मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि ये बेज़ुबान जानवर या तो सड़कों पर दर-बदर की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, या फिर मानव क्रूरता का शिकार हो रहे हैं।

हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ इंसान ने विज्ञान और तकनीक के सहारे चाँद और मंगल तक की यात्रा कर ली है। लेकिन इस विकास की दौड़ में हम कुछ ऐसे प्राणियों को भूलते जा रहे हैं जो हमारे पर्यावरण की संतुलन श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं — वे बेज़ुबान जानवर जो न तो बोल सकते हैं, न शिकायत कर सकते हैं और न ही अपने हक़ की माँग कर सकते हैं।

में ग्वालियर की जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ के कई लोगों ने स्ट्रीट डॉग के लिए रहने और उनके खाने की व्यवस्था कर रखी है। यह लेख उसी को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पिछले कई सालों से में स्वयं और अन्य लोगों ने इन बेज़ुबानों के लिए एक परिवार जैसा माहौल रखा। हमारे ही मुहल्ले का लालू और सफ़ेदी जो मेरी बाइक और कार की हॉर्न सुनकर सीधे घर के नीचे आ जाती, लेकिन अब नगर निगम की टीम ने ना जाने उन्हें किस मुहल्ले में जाकर छोड़ दिया। जबकि वें यह ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी बेज़ुबान अपने घर के अलावा कहीं और नहीं रह सकते।

पिछले दिनों मेरे घर की खिड़की में एक कबूतर ने दो अंडे दिए। रोज़ आकर कबूतर का बैठना और अपने अंडों को निहारना मुझे सुकून देता था। एक दिन मैने ना जाने क्यों उनके अंडों को बिना टच किए एक घोंसले में रख दिया। शायद यह मेरी सबसे बड़ी ग़लती थी। बेज़ुबान खुद अपना घर बना लेते हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं। बस वें हम मनुष्यों से एक संवेदना ज़रूर चाहते हैं। उस दिन के बाद वो कबूतर अपने अंडों को देखने नहीं आई।

पशु — हमारे पर्यावरण की रीढ़

पशु और पक्षी न केवल जैव विविधता का हिस्सा हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अपरिहार्य हैं। गाय, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, हाथी, चिड़ियाँ, और कई अन्य प्रजातियाँ — हर एक का अपना महत्व है। जैसे मधुमक्खियाँ परागण के माध्यम से फसलों को बढ़ावा देती हैं, वैसे ही चिड़ियाँ और कीट मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि ये बेज़ुबान जानवर या तो सड़कों पर दर-बदर की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, या फिर मानव क्रूरता का शिकार हो रहे हैं।

भारत में बेज़ुबानों की स्थिति — कुछ चौंकाने वाले आँकड़े

1. सड़क दुर्घटनाओं में मौत

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और एनजीओ पीपल फ़ॉर एनिमल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल देश में 25 लाख से अधिक जानवर सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इनमें कुत्ते, गाय, बकरी और सांड जैसे पालतू जानवर प्रमुख हैं।

2. अवैध पशु व्यापार और शोषण

भारत में हर साल लाखों जानवरों का अवैध व्यापार किया जाता है। वाइल्ड लाइफ़ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) के मुताबिक़ 2023 में ही 3,000 से अधिक केस अवैध तस्करी के दर्ज हुए।

3. बेसहारा पशुओं की संख्या

2022 में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 1.8 करोड़ बेसहारा पशु हैं जिनमें अधिकतर गाय और कुत्ते हैं।

4. बिल्ली और कुत्तों को छोड़ने की प्रवृत्ति

लॉकडाउन के बाद शहरी इलाक़ों में पालतू जानवरों को छोड़ने की घटनाओं में 40 प्रति. तक वृद्धि देखी गई। ये जानवर सड़कों पर दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

बेज़ुबानों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी

1. **संवेदनशीलता का अभाव**-हमारा समाज अक्सर जानवरों को इंसानों से निम्न स्तर का समझता है। स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर संवेदनशीलता की कमी है। बच्चों को जानवरों के साथ करुणा से व्यवहार करना नहीं सिखाया जाता।
2. **कानून तो हैं, पर पालन नहीं**-भारत में पशु संरक्षण के लिए कई कानून हैं
   प्रीवेन्शन ऑफ़ क्रुयेलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960
   वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972
   इन कानूनों के तहत जानवरों के साथ क्रूरता करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका पालन बहुत कम होता है।
3. **निगमों की लापरवाही**-नगर निगमों और नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी है कि वे आवारा पशुओं के लिए आश्रय गृह (shelter homes) बनाएँ। लेकिन अधिकतर शहरों में ये सुविधा या तो है ही नहीं या नाममात्र की है।

कौन उठा रहा है ज़िम्मेदारी?

कुछ संगठन और व्यक्ति अपने स्तर पर इन बेज़ुबानों के लिए काम कर रहे हैं-

1. पीपल फ़ॉर एनिमल्स (पीएफए)

मेनका गांधी द्वारा स्थापित यह संस्था देशभर में घायल और बेसहारा जानवरों के लिए कार्य कर रही है। इसके 26 से अधिक केंद्र भारत में सक्रिय हैं।

2. ब्लू क्रॉस ऑफ़ इंडिया

चेन्नई स्थित यह संस्था भारत की पहली पशु कल्याण संस्था है जिसने सैकड़ों पशुओं को जीवनदान दिया है।

3. स्ट्रे रिलीफ़ एंड एनिमल्स वेलफ़ेयर (स्ट्रॉ)

दिल्ली आधारित यह संस्था स्कूलों में बच्चों को जानवरों के प्रति करुणा सिखाने के लिए कार्यक्रम चलाती है।

आम नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं?

1. बेज़ुबानों को खाना-पानी दें

गर्मियों में घर के बाहर एक पानी का बर्तन रखना, ठंड में किसी जानवर को कम्बल देना — ये छोटे-छोटे कदम जान बचा सकते हैं।

2. सड़कों पर वाहन चलाते समय सतर्कता

रात के समय वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। कई बार जानवर सड़कों पर आराम कर रहे होते हैं।

3. स्थानीय एनजीओ से जुड़ना

अपने क्षेत्र की किसी पशुसेवी संस्था से जुड़कर आप वॉलंटियर बन सकते हैं।

4. पालतू जानवर को कभी न छोड़ें

यदि आपने किसी जानवर को अपनाया है, तो उसका पालन-पोषण आजीवन करें। जानवर कोई खिलौना नहीं है जिसे मन भर जाने पर फेंक दिया जाए।

5. शिक्षा में करुणा को शामिल करें

बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही जानवरों से प्रेम करना सिखाएँ। समानुभूति की भावना से समाज में परिवर्तन आ सकता है।

सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग

आज का युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे माध्यमों पर कई पशुसेवी वीडियो वायरल होते हैं। यदि हम इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग जागरूकता फैलाने के लिए करें, तो लाखों लोगों तक संदेश पहुँचाया जा सकता है।

करुणा ही समाधान है

इस धरती पर इंसान अकेला प्राणी नहीं है जिसे जीने का अधिकार है। जानवर भी इस धरती के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने हम। वे बोल नहीं सकते, मगर उनका दर्द असली होता है। हमारा धर्म, संस्कृति और मानवता सभी हमें यही सिखाते हैं — जियो और जीने दो। इसलिए अगली बार जब आप किसी घायल या भूखे जानवर को देखें, तो नजरें फेरने की बजाय दिल से सोचिए — क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं?

आपका एक छोटा सा प्रयास किसी बेज़ुबान की ज़िंदगी बचा सकता है।

तो आइए, इन बेज़ुबानों के लिए अपने दिल में एक कोना सुरक्षित रखें!

परिंदों की पुकार

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तम्भकार हैं।

कोई पानी डाल दे तो मैं भी चौंच भर पीलूं

गर्मी अब सिर्फ तापमान नहीं रही, यह अब एक त्रासदी बन गई है — खासकर उनके लिए जिनकी आवाज़ न अख़बार में छपती है, न टीवी पर आती है, और न ही सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में। बात हो रही है उन छोटे-छोटे परिंदों की, जो इस तेज़ धूप, सूखी हवाओं और कंक्रीट के जंगल में चुपचाप प्यास से तड़प कर मर जाते हैं। 'कोई पानी डाल दे तो मैं भी चौंच भर पीलूं...' — यह पंक्ति अब किसी कविता की कोमल कल्पना नहीं रही, यह एक जीवित सच्चाई है, एक निरीह पुकार, जो हर दोपहर किसी छत पर, किसी सूखी डाल पर, किसी तपती खिड़की की जाली के पीछे से उठती है।

शहरों ने छीन ली परिंदों की छांव

हमने पेड़ काटे, तालाब पाटे, छज्जों को सीमेंट से बंद कर दिया और टीन की छतों से सूरज को और गर्म कर दिया। आधुनिकता के नाम पर हमने अपने घरों को एसी से ठंडा किया, लेकिन परिंदों के लिए एक घूंट पानी छोड़ना भूल गए।पक्षियों के घोंसले बनाने की जगहें कम होती जा रही हैं। अब उनके लिए न पेड़ बचे, न परछाई, न ही वह परंपरागत संस्कृति जिसमें हर घर की मुंडेर पर मिट्टी का एक कटोरा पानी से भरा होता था।

प्यास से मरते परिंदे- आँकड़े नहीं, चेतावनी हैं

कई पर्यावरण संस्थाएं बता रही हैं कि गर्मी में पक्षियों की मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। खासतौर पर गौरैया, कबूतर, मैना, बुलबुल जैसे छोटे पक्षी गर्मी की दोपहर में बेहोश होकर गिर जाते हैं, और यदि उन्हें समय पर पानी न मिले, तो मर भी जाते हैं। पर क्या इनकी मौतें किसी समाचार का हिस्सा बनती हैं? क्या इन पर कोई सरकारी घोषणा होती है? क्या इनका कोई 'एनजीओ सम्मेलन' बुलाया जाता है?

पक्षी नहीं बचेंगे, तो हम भी नहीं बचेंगे

परिंदे सिर्फ आसमान की शोभा नहीं हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। वे कीट नियंत्रण करते हैं, परागण में मदद करते हैं, बीज फैलाते हैं, और सबसे ज़रूरी — वे जीवन के संगीत को बनाए रखते हैं। अगर पक्षी गायब हो गए, तो यह धरती और अधिक वीरान हो जाएगी — और हम भी।

हमें यह समझना होगा कि ये नन्हें जीव प्रकृति की बड़ी चेतावनियाँ लेकर आते हैं। जब वे प्यास से मर रहे हैं, तो समझिए कि पानी की कमी अब हमारी ओर भी बढ़ रही है।

'बर्ड फ्रेंडली' नहीं, 'लाइफ फ्रेंडली' बनिए

आज ज़रूरत इस बात की है कि हम 'बर्ड फ्रेंडली' समाज बनें। यह कोई बड़ा आंदोलन नहीं, सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ें हैं। छत या बालकनी में एक मिट्टी का पानी भरा कटोरा रखें। पेड़ लगाएं, खासतौर पर नीम, पीपल, अमरूद जैसे देशी वृक्ष। बच्चों को परिंदों के बारे में बताएं — दया, संवेदना और जुड़ाव सिखाएं। गर्मियों में पशु-पक्षियों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था करें। मंदिरों-मस्जिदों-गुरुद्वारों जैसे स्थलों को भी प्रेरित करें कि वे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। यह काम किसी सरकार का इंतज़ार नहीं करता। यह आपके हाथ में है।

व्यंग्य की एक बूंद- 'बिजली का बिल तो भरेंगे, पर परिंदों को पानी नहीं देंगे'

हम एसी चलाने के लिए हज़ारों की बिजली जला देंगे, लेकिन एक कटोरा पानी रखने में कंजूसी कर जाते हैं। हम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों बहा देंगे, लेकिन स्मार्टनेस इतनी नहीं कि बेजुबानों के लिए भी कुछ छोड़ सकें। हमारे समाज में अब 'करुणा' भी इंस्टाग्राम रील बन गई है — दिखावा भर, असर नहीं।

शहर की छत से गाँव के चौपाल तक — एक पुकार

गाँवों में भी अब पुराने तालाब सूख रहे हैं, बावड़ियाँ टूट चुकी हैं, और पशु-पक्षियों के लिए पीने का पानी अब मुश्किल हो गया है। एक समय था जब गाँव में हर कुएँ की मेड़ पर परिंदे पानी पीने आते थे। आज वही कुएँ सीमेंट से बंद कर दिए गए हैं। शहरों ने गाँवों को 'विकास' तो दिया, पर वह विकास पक्षियों के लिए विनाश बन गया।

जलवायु परिवर्तन- परिंदों से पहले असर इनके पड़ता है

जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला और सीधा असर बेजुबानों पर पड़ता है। तापमान में जरा सी वृद्धि भी इनके लिए प्राणघातक हो सकती है। इंसान तो पंखा चला लेता है, बर्फ खा लेता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। पर चिड़िया कहां जाए? कबूतर किससे कहे कि वह प्यासा है?

समापन- क्या हम सच में इंसान हैं?

हम खुद को बुद्धिजीवी, संवेदनशील, शिक्षित और विकसित कहते हैं — लेकिन क्या कोई भी ऐसी सभ्यता वाकई 'विकसित' कहलाने लायक है जो अपने साथ रहने वाले जीवों को मरता देखे और फिर भी चुप रहे? हर गर्मी हमें यह सोचने का मौका देती है — कि इस बार क्या हम अपने घर की छत, खिड़की, बालकनी या आंगन में एक कोना ऐसा बना सकते हैं जहां कोई छोटा परिंदा अपनी चौंच भर पानी पी सके?

शायद जवाब देने की ज़रूरत नहीं। बस अगली बार जब सूरज सिर पर हो, तो किसी परिंदे की ओर देखिए...और याद रखिए —

कोई पानी डाल दे तो मैं भी चौंच भर पीलूं...

बौद्धिक विरासत

संदीप सृजन

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को धरोहर

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत ने विश्व मंच पर एक बार फिर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना न केवल भारत के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि यह मानव सभ्यता के बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इन दोनों ग्रंथों का यूनेस्को धरोहर में शामिल होना, इन ग्रंथों के सांस्कृतिक और दार्शनिक योगदान के वैश्विक प्रभाव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण के महत्व को दर्शाता है।

यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम, जो 1992 में शुरू हुआ, विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षित करने और उनकी वैश्विक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक दस्तावेजों को विस्मृति से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिए उनकी प्रासंगिकता बनाए रखना है। इस रजिस्टर में शामिल होने वाली धरोहरें मानव सभ्यता के लिए असाधारण महत्व रखती हैं, और श्रीमद्भगवद्गीता व नाट्यशास्त्र का इसमें शामिल होना भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता-आध्यात्मिक और दार्शनिक धरोहर

श्रीमद्भगवद्गीता, जिसे अक्सर केवल गीता कहा जाता है, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक अनमोल रत्न है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसमें भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश शामिल है। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्तव्य (धर्म), ज्ञान (ज्ञान योग), भक्ति (भक्ति योग), और कर्म (कर्म योग) पर गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं।

गीता का केंद्रीय संदेश मानव जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने के लिए है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्काम भाव से करने, आत्म-साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की प्रेरणा देता है। गीता में तीन गुणों (सत्व, रजस, तमस) का उल्लेख और सात्विक बुद्धि की महत्ता पर बल दिया गया है, जो मानव को धर्म और अधर्म, बंधन और मोक्ष के बीच अंतर समझने में मदद करती है।

यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता का शामिल होना इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। यह ग्रंथ न केवल हिंदू धर्म का आधार है, बल्कि इसमें वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक जैसे विविध भारतीय दार्शनिक विचारों का समन्वय है। गीता का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है और यह विश्व भर के दार्शनिकों, विचारकों और सामान्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।

नाट्यशास्त्र-भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र का आधार

भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं का एक प्राचीन विश्वकोश है। यह नाटक, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस (सौंदर्य अनुभव), और भाव (भावनात्मक अभिव्यक्ति) जैसे विषयों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नाट्यशास्त्र को भारतीय रंगमंच, काव्यशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र का आधार माना जाता है। इसमें रस सिद्धांत, जो नौ रसों (शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, और शांत) को परिभाषित करता है, ने भारतीय कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है।

नाट्यशास्त्र केवल एक तकनीकी ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण चेतना का प्रतीक है। इसने न केवल भारत में, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी प्रदर्शन कलाओं को आकार दिया है। नाट्यशास्त्र में वर्णित सिद्धांत आज भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य (जैसे भरतनाट्यम, कथक, और ओडिसी) और रंगमंच में जीवंत हैं। यूनेस्को द्वारा नाट्यशास्त्र को मान्यता देना भारतीय कला और संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह ग्रंथ मानव अभिव्यक्ति और सौंदर्यशास्त्र के क्षेत्र में भारत के योगदान को रेखांकित करता है।

वैश्विक मंच पर बौद्धिक और सांस्कृतिक छाप

श्रीमद्भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होना कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों का यूनेस्को द्वारा सम्मानित होना भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की शाश्वत ज्ञान और सांस्कृतिक प्रतिभा का सम्मान है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का उद्देश्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करना है। गीता और नाट्यशास्त्र के शामिल होने से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों और उनके ज्ञान को डिजिटल और भौतिक रूप में संरक्षित करने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करता है कि ये धरोहरें भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें।

गीता और नाट्यशास्त्र का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन विश्व भर में दार्शनिक और सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करता है। गीता का संदेश और नाट्यशास्त्र के सौंदर्यशास्त्र विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक हैं, जो मानवता के साझा मूल्यों को मजबूत करते हैं। यूनेस्को की मान्यता से इन ग्रंथों पर वैश्विक स्तर पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। विद्वान और शोधकर्ता इन ग्रंथों के दार्शनिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को और गहराई से समझ सकेंगे। गीता और नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथ भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक हैं, जो विश्व में भारत की छवि को और सशक्त करते हैं।

गीता और नाट्यशास्त्र के शामिल होने के साथ, भारत की कुल 14 कृतियां अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का हिस्सा हैं। इससे पहले, ऋग्वेद (2007 में शामिल), तवांग शास्त्र, और संत तुकाराम की अभंग रचनाएं भी इस सूची में स्थान पा चुकी हैं। यह भारत की समृद्ध साहित्यिक और दार्शनिक परंपरा का प्रमाण है।गीता और नाट्यशास्त्र का यूनेस्को धरोहर में शामिल होना केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।

भारत को इन ग्रंथों के संरक्षण, प्रचार और प्रसार के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। डिजिटल संग्रह, अनुवाद, और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में इन ग्रंथों को शामिल करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। साथ ही, इन ग्रंथों के मूल्यों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना भी आवश्यक है, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। ये ग्रंथ न केवल भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक चेतना के आधार हैं, बल्कि वे मानव सभ्यता के लिए भी अमूल्य धरोहर हैं। इस मान्यता से न केवल इन ग्रंथों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय दर्शन और कला की समझ को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, जो हमें अपनी समृद्ध विरासत को और अधिक जिम्मेदारी के साथ संजोने और साझा करने की प्रेरणा देता है।

दोपहर में सडक़ें सूनीं, बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी

तापमान बढ़ा, गर्मी के कारण शहर की सड़कों पर दोपहर में कर्फ्यू जैसे हालात

बैतूल। जिले का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, ऐसे में हर कोई भीषण गर्मी व सूरज की तपिश से परेशान है। इस सीजन में रविवार को सबसे गर्म दिन रहा। आज रिवार को गर्मी ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया तो लोग हलाकान हो उठे। स्थिति यह रही कि शहर में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बाजार की सडक़ पर कफ्यू जैसे हालात देखने को मिले। हालांकि वैवाहिक सीजन शुरू होने से कुछ दुकानों पर जरुर ग्राहकों को देखा गया, लेकिन गर्मी का असर शाम 6 बजे के बाद कुछ हद तक कम होने पर ही लोगों का निकलना शुरु हुआ। हालात यह है कि धूप से बचने के लिए लोग विभिन्न जतन कर रहे हैं। आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। रविवार को तापमान बढऩे और तेज धूप खिलने से मुख्य सडक़े दोपहर में सूनी रही, और गर्म हवा का दौर जारी

रहा है।जिससे बाजार में भी ग्राहक की संख्या कम ही नजर आई। रविवार को अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। आगामी समय में लू भी चल सकती है।

घरों में 24 घंटे कूलर, पंखे व एसी का उपयोग : विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि आमतौर पर गर्मियों के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है। जिन घरों में हर दिन, आम दिनों में 5 से 6 यूनिट बिजली की खपत होती है, जो बढक़र 8 से 10 यूनिट तक पहुंच जाती है। इस समय मूंग का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में किसानों को विद्युत पंप चलाने, जहां 10 घंटे की नियमित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, तो वहीं घरेलू फीडरों पर भी गर्मी के कारण अत्यधिक दबाव बना हुआ है, जिससे ट्रांसफार्मरों में ओवरलोड होने पर फाल्ट जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। घरों में कूलर, पंखे व एसी का उपयोग 24 घंटे हो रहा हैं।

शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़: इस समय शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ नजर आई। भीषण गर्मी में अपना गला तर करने के लिए शहर सहित ग्रामीण दुकानों पर पहुंचकर गर्मी से राहत पा रहे है। गर्मी बढऩे के कारण शीतल पेय का व्यापार भी गति पकड़ता जा रहा है। इस समय पायनेपल, मौसमी, गन्ना, अनार, आम के जूस के अलावा विभिन्न कंपनियों की कोल्ड्रिंग की भी बिक्री बढ़ गई है। बाजार में विभिन्न फलों का जूस जहां 20 से 50 रुपए प्रति ग्लास मिल रहा है।

इस माह बना सकती है गर्मी नया रिकॉर्ड : बता दें कि अचानक बीते दो दिनों से शहर के तापमान में एकाएक वृद्धि होती जा रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन के सबसे गर्म दिनों में गिना गया। हालांकि अभी गर्मी से निजात मिलना संभव नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो हीट वेब की शुरुआत हुई है। तापमान में बढ़ोतरी का क्रम अभी जारी रहेगा। मौसम अनुमान के अनुसार तापमान अभी और बढ़ेगा और यह 42 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसी माह गर्मी नया रिकॉर्ड बना सकती है।

दोपहर में सडक़ों पर कर्फ्यू जैसे हालात .....

लोग तेज धूप से बचने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे है। सुबह 8-9 बजे से ही धूप चुभने लगती है। शाम 5 बजे तक तेज धूप खिलने से गर्मी के तेवर बहुत अधिक देखने को मिल रहे है। दोपहर के समय गर्मी के कारण रास्ते भी सूने हो जाते है। जिससे सडक़ों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आते है। गर्मी के कारण लोग घरों में दूबकने के लिए मजबूर है। लोग घर से निकलते समय चश्मे, गम्छे का सहारा लेने मजबूर होना पड़ रहा। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी अधिक व तेज धूप से बचने का प्रयास करें। अधिक मात्रा में पानी पीएं। खाली पेट घर से बाहर न निकलें। थकावट व कमजोरी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। चेहरे व सिर को ढंककर निकलें।

लू, उल्टी, दस्त के मरीजों की भीड़ .....

गर्मी बढ़ने से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हीट वेव चलने से कोई ना कोई गर्मी के कारण बीमार पड़ा है। जिला अस्पताल में रोजाना 500 से 600 मरीज रोजाना पहुंच रहे है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज उल्टी, दस्त, लू, डिहाइड्रेशन के हैं। जिन्हें डॉक्टरों द्वारा ओआरएस का घोल पीने, साफ व स्वच्छ पानी का सेवन करने, बच्चों को पानी उबालकर व छानकर पिलाने, भीषण गर्मी में घरों में ही रहने, गर्म हवाओं से सिर व आंखों का बचाव करने के लिए सिर पर कपड़ा या टोपी लगाने, बाजार की तली-गली चीजों से परहेज करने की सलाह दी जा रही है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. जगदीश घोरे के अनुसार गर्मी के इस दौर में सावधानी की बहुत आवश्यकता है। इस समय शरीर को पानी की आवश्यकता अधिक लगती है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए।

शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की जेईई में शानदार सफलता

- 86 छात्रों को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की संभावना,
- 28 ने क्वालीफाई की एडवांस परीक्षा
- प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने विद्यार्थियों का बढ़ाया था मनोबल

बैतूल। जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा ने बताया कि कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में वर्ष भर चली तैयारी और परीक्षा उपरांत संचालित निशुल्क कोचिंग के सकारात्मक परिणाम जेईई परीक्षा के दोनों चरणों जनवरी एवं अप्रैल के परिणामों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए हैं। विदित है कि पूर्व में प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने पीएमश्री महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जेईई और नीट की कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों से चर्चा कर उनका मनोबल बढ़ाया था। जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों ने यह उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। जिला शिक्षा

अधिकारी कार्यालय के विभागीय अधिकारी सुबोध शर्मा ने बताया कि शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों द्वारा वर्ष पर्यन्त, कक्षा अध्यापन के अतिरिक्त जेईई और नीट की तैयारी कराई गई। साथ ही परीक्षा के पश्चात जिले के समस्त विकासखंड मुख्यालय पर निशुल्क कोचिंग में इन शिक्षकों द्वारा अपने कार्य के साथ अवकाश के दिनों में भी नियमित अध्ययन कराया गया। बच्चों को उपलब्ध कराए गए पूर्व वर्षों के हल किए हुए प्रश्न पत्र, टेस्ट के माध्यम से कराई गई तैयारी, विशिष्ट उत्कृष्ट टॉपिक पर प्रदान किए गए मार्गदर्शन इत्यादि से जेईई की परीक्षा के दो चरणों, जिनमें प्रथम चरण जनवरी एवं द्वितीय चरण अप्रैल में संपन्न परीक्षा के परिणाम को मिलाकर, अभी तक एकत्रित जानकारी अनुसार जिले से इन बच्चों में से 86 बच्चों को प्राप्त अंकों के आधार पर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना संभावित है। यही नहीं इनमें से 28 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। इस संख्या में बढ़ोतरी होना संभावित है। परीक्षा में सफल रहे इन समस्त विद्यार्थियों, जिला स्तर पर विकासखंड मुख्यालय बैतूल में शासकीय एमएलबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित निशुल्क कोचिंग के नोडल अधिकारी नीलेश्वर कलभोर, सभी विकासखंड नोडल अधिकारियों, इन कक्षाओं एवं निशुल्क कोचिंग में अध्यापन करने वाले समस्त शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बधाई दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश संबंधी परीक्षा नीट के लिए निशुल्क कोचिंग एमएलबी में संचालित है और परीक्षा तक इसे संचालित रखा जाएगा।

आरडी कोचिंग का जेईई मेन्स सेशन-2 का रहा उत्कृष्ट परिणाम

- सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को किया सम्मानित,
- मिलन मोहने ने हासिल किए 99.97 परसेंटाइल

बैतूल। कोचिंग संस्थान आरडीसीसी बैतूल का जेईई मेन्स सेशन-2 का शानदार परीक्षा परिणाम रहा। उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं का कोचिंग प्रबंधन एवं शिक्षकों ने सम्मानित कर हौसला बढ़ाया साथ ही विद्यार्थियों ने भी खुशियां मनाई। आरडी कोचिंग क्लासेस बैतूल के विद्यार्थी मिलन मोहने ने गणित में 100 परसेंटाईल के साथ ओव्हर ऑल 99.97 परसेन्टाईल हासिल कर जिले का नाम रौशन किया। जेईई मेन्स

सेशन-2 में 99.97 परसेन्टाईल हासिल करने वाले मेधावी छात्र मिलन मोहने ने कहा कि उत्कृष्ट सफलता का यह सफर आसान नहीं था। लेकिन आरडीसीसी के अनुभवी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन, टेस्ट सीरीज का सतत अभ्यास और पर्सनल गाइडेंस ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया है। सफलता प्राप्त करने वाले अन्य छात्र-छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर श्रीमती ऋचा खण्डेलवाल द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन देकर परीक्षा के दबाव से निपटने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में सतत अध्ययन, डाउट क्लीयरेंस तथा लगातार मोटिवेशन से यह सफलता हासिल की है। विद्यार्थियों का मानना है कि आर.डी.कोचिंग क्लासेस में छात्र और शिक्षक सिर्फ क्लास रूम तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि एक पारिवारिक माहौल में रहकर पढ़ाई करते है। कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर श्रीमती ऋचा खण्डेलवाल ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत आने वाले समय में सफलता के नए कीर्तिमान हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि हमे गर्व है कि आरडी कोचिंग के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे है। डायरेक्टर श्रीमती खण्डेलवाल ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

इन विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

आरडी कोचिंग क्लासेस में आयोजित सम्मान समारोह में जेईई मेन्स सेशन-2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। जेईई मेन्स सेशन-2 में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वालों में मिलन मोहने, ख्याति मानकर, प्रिंस वराठे, दीपाली चौहान, कुलदीप साहू, प्रियांषी वर्मा, रामकृष्ण सिरसाम, यशस्वी मेश्राम, सुहानी अमित चौधरी, आयमेन जावेद, हिमांशी डोंगरदिये, श्रेयांश सोनी, आर्यन राठौर, इशिता पंवार, माही उदासी, मोहित दाते, यशस्वी अडलक, आदित विकेश शाह, अंशिका राजेश, अरहत रंजीत निरगुले, आर्या धोटे, चित्रांश धोटे, गौरव साहू, के राहुल, लक्ष्य परिहार, लावण्या चौकीकर, मयूर मानकर, पार्थ चौकीकर, पुष्पराज साहू, उत्कृष्ट आहूजा, चहक धोटे शामिल है।

ज्ञान रत्नों की खान थी दादीजी : केंद्रीय मंत्री डीडी उईके

दादीजी के श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री, रक्तदान शिविर का भी हुआ आयोजन

बैतूल । अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्माकुमारीज़ की मुख्य प्रशासिका आदरणीया राजयोगिनि दादी रतन मोहिनी जी ने 8 अप्रैल 2025 को अपने 102 वर्ष की आयु में रहते अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। दिनांक 20 अप्रैल दिन रविवार को दादीजी के निमित्त विश्व के 140 से अधिक देशों में ब्रह्माकुमारीज़ के 5500 सेवाकेंद्रों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है । इसी उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारीज़ के स्थानीय सेवाकेंद्र भाग्यविधाता भवन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डी डी उईके भी उपस्थित रहे। मंत्री जी ने दादीजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दादीजी का जीवन त्याग तपस्या व निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है जो हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। दादी जी ने अपने आध्यात्मिक दिव्य आभा से सारे संसार को प्रकाशित किया और उनके आचरण का अनुकरण करते हुए हजारों ब्रह्माकुमारी बहने अध्यात्म के मार्ग पर विश्व परिवर्तन के दिव्य कार्य को साकार रूप देने में लगी हुई है। ऐसी दिव्य विभूति का मुझे सान्निध्य प्राप्त हुआ और उनसे मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं ।

नहाते समय ताप्ती नदी में डूबा 60 वर्षीय बुजुर्ग, मौत

बैतूल। ताप्ती नदी में डूबने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान भद्दू पिता गुन्नू कासदे के रूप में हुई है। वह ग्राम पीपला थाना बैतूल बाजार का रहने वाला था। रविवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच भद्दू परिवार को नहाने जाने की बात कहकर घर से निकला। नदी में नहाते समय उसकी धोती पैरों में फंस गई। गहरे पानी में जाने पर वह पैर नहीं चला पाया और डूब गया। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वह नहाने नहीं बल्कि मछली पकडऩे गया था। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह पूरी तरह डूब चुका था। बाद में किसी तरह शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को जिला अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

बैतूल। नागपुर नेशनल हाईवे पर सडक़ हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान मिलानपुर निवासी घनश्याम सुनारे के रूप में हुई है। घटना शनिवार-रविवार की दरमियानी रात की है। हादसे के समय घनश्याम एक सामाजिक कार्यक्रम से घर लौटे थे। रात करीब एक बजे उन्होंने परिजनों को बताया कि वे मवेशी बांधने के लिए खेत जा रहे हैं। वे स्कूटी से बैतूल बाजार जोड़ को पार कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। रात करीब दो बजे किसी ने घनश्याम के घायल होने की सूचना परिजनों को दी। उनके बेटे संतोष और अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल घनश्याम को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र वर्मा के अनुसार, डॉक्टरों ने घनश्याम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन ने उन्हें करीब सौ मीटर तक घसीटा। इसके निशान हाईवे पर नजर आ रहे है।

जहर खाने से मजदूर की मौत

बैतूल। मेहतपुर गांव में एक 42 साल के व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक करन सिंह कुमरे ने बुधवार शाम को अपने घर में जहर खा लिया था। जानकारी मिलते ही परिजनों ने उन्हें भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद 108 एंबुलेंस से उन्हें बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चार दिन तक चले इलाज के बाद रविवार दोपहर करीब 1 बजे उनकी मौत हो गई। घटना मृतक के परिजनों ने बताया कि करन सिंह मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे।

वाणी श्रीवास्तव का दीक्षांत समारोह सम्पन्न

'यह डिग्री केवल मेरी नहीं, पूरे परिवार की उपलब्धि है' : डॉ. वाणी

बैतूल। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की 2019 बैच की छात्रा डॉ. वाणी श्रीवास्तव ने अपने MBBS पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद 12 अप्रैल 2025 को आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लेकर अपनी उपलब्धि को अपने परिवार के चरणों में समर्पित कर भावुक कर देने वाला उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉ. वाणी बैतूल निवासी श्री नवीन श्रीवास्तव (जनरल मैनेजर, जिविशा हर्बल) एवं श्रीमती अलका श्रीवास्तव की सुपुत्री तथा नवनीता -मुकेश गुमास्ता स्टेनो कलेक्टर बैतूल, प्रवीण श्रीवास्तव एडवोकेट, सुवीण श्रीवास्तव चेयरमैन आयाम एवं अभिषेक श्रीवास्तव वरिष्ठ जर्नालिस्ट की भतीजी हैं.। उनकी इस उपलब्धि पर समस्त गुरुकृपा परिवार गौरवान्वित है।

दीक्षांत समारोह में डिग्री ग्रहण करते हुए डॉ. वाणी ने कहा कि यह डिग्री मैंने नहीं, हमने प्राप्त की है...

हां माना रात भर पढ़ा तो मेने, पर आखें तो आपकी भी नहीं सोई

उसदिन खुश थे हम सभी बहुत, मगर आखें आपकी खूब रोई..

उनके इस उद्गार ने वहाँ उपस्थित परिजनों को गहरे भाव में डुबो दिया और समारोह एक पारिवारिक उत्सव में परिवर्तित हो गया।

--राजसी आयोजन बना स्मृति का उत्सव-- इस विशेष अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए डॉ. वाणी ने दीक्षांत से एक दिन पूर्व, रीवा के Namah Resort में एक भव्य पारिवारिक डिनर एवं पूल पार्टी का आयोजन किया, जो केवल परिवार के लिए आरक्षित था। इस आयोजन ने पूरे परिवार को हर्ष और गर्व के मधुर क्षणों में डुबो दिया। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर वरिष्ठजनों तक सभी ने आत्मीयता और आनंद के साथ सहभागिता की।

--साहस का प्रतीक बने छोटे भाई अभिषेक-- परिवार के छोटे भाई श्री अभिषेक, जो कुछ समय पूर्व एक सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे, उनके समारोह में सक्रिय रूप से उपस्थित रहने और हर क्षण को पूरे उत्साह से जीने ने सभी को भावविभोर कर दिया। दर्द को दरकिनार कर उनका मुस्कुराना और परिवार के साथ खड़ा रहना, वास्तव में साहस और प्रेम का प्रतीक बन गया।

डॉ. संदीप गोहे की अगुवाई में एसआईएफ बैतूल टीम पहुंची दिल्ली

जंतर-मंतर पर जुटे हज़ारों पुरुष, पुरुष आयोग और समान कानूनों की उठी मांग

बैतूल। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को पुरुषों के अधिकारों और पारिवारिक संतुलन की मांग को लेकर आयोजित 'पुरुष सत्याग्रह आंदोलन ने इतिहास रच दिया। सेव फैमिली फाऊंडेशन के तत्वावधान में और सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट से जुड़ी 40 से अधिक संगठनों की भागीदारी में यह अब तक का सबसे बड़ा पुरुष-समर्थक आंदोलन बना। इस ऐतिहासिक सत्याग्रह में देशभर से हज़ारों पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों ने एकत्र होकर समाज में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति, जेंडर न्यूट्रल कानूनों और पुरुष आयोग की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। बैतूल जिले से एसआईएफ बैतूल टीम ने इस आंदोलन में विशेष भागीदारी निभाई। टीम के संस्थापक डॉ. संदीप गोहे के नेतृत्व में बैतूल से एक सशक्त टोली दिल्ली पहुंची और मंच से पुरुषों की पीड़ा और मौन दर्द को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। मंच से संबोधित करते हुए डॉ. संदीप गोहे ने पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में पुरुषों की मानसिक पीड़ा को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। वह

लगातार कानूनी, पारिवारिक और सामाजिक दबावों से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से वे अवसाद और आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पुरुषों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की अपील की। इस आंदोलन में बैतूल से भाग लेने वालों में डॉ. संदीप गोहे के साथ चंद्रप्रकाश झारे, डॉ. जावेद खान, डॉ. किशोर पांडोले, राजेश उपराले, विजय साहू, मुकेश झारखंडे, हरिप्रसाद पिपले, शंकर मालवीय, रूपेश पवार और कचेश्वर गुर्जर शामिल रहे। इन सभी ने मिलकर बैतूल की दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई और आंदोलन को सशक्त बनाया। आंदोलन के दौरान पुरुषों के समर्थन में चार प्रमुख मांगे भी रखी गईं। देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन, जेंडर न्यूट्रल कानूनों में संतुलन और उनके दुरुपयोग की रोकथाम, पति-पत्नी जैसे शब्दों की जगह सहभागी या संपूर्णक जैसे समावेशी शब्दों का प्रयोग और संयुक्त अभिभावकता को सुनिश्चित करने हेतु समुचित कानूनों की स्थापना।

जिला अस्पताल में 7 घंटे से बिजली गुल, मरीज थे परेशान

बैतूल। जिला अस्पताल में सुबह साढ़े 8 बजे से बिजली बंद है। लाइन में फाल्ट आने से कई वार्डों में अंधेरा छाया हुआ है। गर्मी के चलते कूलर, पंखे बंद हो गये, जिससे मरीज बेहाल हुए। जनरेटर सेट और ट्रांसफॉर्मर में एक साथ फॉल्ट आने से ये समस्या हुई है। इधर बिजली की समस्या से अस्पताल की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आयुष्मान योजना, एक्स-रे, डायलिसिस, ट्रॉमा सेंटर और सिटी स्कैन विभाग का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके साथ ही बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। एक जनरेटर की बैटरी काम नहीं कर रही है। डीजी सेट बंद है। आईसीयू का जनरेटर भी खराब है। साथ ही बिजली ट्रांसफॉर्मर में भी समस्या आ गई है। गर्मी के मौसम में पंखे न चलने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों को रैंप से ले जाया जा रहा है। मरीज और उनके परिजनों ने बताया कि गर्मी के कारण उन्हें दिक्कत हो रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी फॉल्ट को ठीक करने में जुटे हैं और शाम तक बिजली के चालू होने की उम्मीद है। सिविल सर्जन डॉ. जगदीश घोरे ने बताया कि अस्पताल के एक जनरेटर की बैटरी काम नहीं कर रही है। डीजी सेट बंद हो गया है। इससे अस्पताल की कुछ सेवाएं प्रभावित हुई है। इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर श्री जैन ने गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने गुरुवार सुबह रिद्धि सिद्धि वेयर हाउस पिड़गांव तथा श्रीनिधि वेयर हाउस पिड़गांव में बनाए गए उपार्जन केंद्रो का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वासुदेव भदोरिया और उप संचालक कृषि श्री जवाहर लाल कास्दे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री जैन ने मौके पर उपस्थित किसानों से चर्चा की और उपार्जन केंद्र पर आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उपार्जन केंद्र के संचालक को निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन के लिए आने वाले किसानों को कोई परेशानी ना आए। उन्होंने कहा कि केंद्र पर आने वाले किसानों के लिए पेयजल, और बैठने के लिए शेड की व्यवस्था करें। कलेक्टर श्री जैन ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को केंद्र पर कम से कम इंतजार करना पड़े यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री जैन ने इस अवसर पर खरीदे गए गेहूं की गुणवत्ता भी देखी। उन्होंने उपार्जन केंद्र में पर्याप्त संख्या में बारदाने, तौलकांटे और नमी मापक यंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी निर्देश दिए।

विशेष शाखा के कार्यों का परीक्षण सूची चस्पा करने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज कलेक्ट्रेट की विशेष शाखा के कार्यो का जायजा लिया । उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि स्वीकृति के आदेश प्राप्त होते हैं वह जानकारी अधीक्षक कार्यालय की दीवार पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था क्रियान्वयन की जाए। जिसमें बैंक व यूआईडी नंबर भी अंकित किये जाएं। शाखा प्रभारी ने अवगत कराया कि हर माह करीबन सौ से दो सौ स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती हैं।

जिला पंचायत सीईओ ने की पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के कार्यों की समीक्षा

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन द्वारा प्रति गुरुवार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत जिले में संचालित सभी गतिविधियों की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासखंडवार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्यान्न उठाव, मोबाइल एप के माध्यम से शालाओं का निरीक्षण, ÷पोषण पखवाडा÷ अभियान तथा जिले में शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नवाचार संबंधी कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य आपूर्ति अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में खाद्यान्न उठाव में समस्या आ रही है उनका त्वरित निराकरण करें। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन सीहोर विकासखंड के ग्राम पाडली स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला की शिक्षिका श्रीमती अर्पणा लवाहे द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत शाला परिसर में बनाई गई मां की बगिया की सराहना की गई। इसके साथ ही आष्ठा विकासखण्ड के चुपाडिया स्थित शासकीय माध्यमिक शाला की प्राचार्य श्रीमती सीमा जैन एवं शिक्षकों, विद्यार्थियों, रसोइयों द्वारा शाला में बनाई गयी माँ की बगिया, पोषण वाटिका, औषधीय वाटिका के संबंध में चर्चा कर प्रोत्साहित किया गया एवं सराहना की गई।

जल गंगा संवर्धन अभियान तहत ग्राम छुलेटा में सामूहिक श्रमदान

विदिशा (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था आवरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में ग्राम छुलेटा में जल संवर्धन अभियान अंतर्गत सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम में जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवन हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। श्रमदान के अंतर्गत ग्राम के पास स्थित बावड़ी की साफ-सफाई की गई। साथ ही सभी ग्राम वासियों व सदस्यों के साथ शपथ का आयोजन कर जल संरक्षण का महत्व बताया।इस अवसर पर संस्था प्रमुख अमित शर्मा ने बताया कि जल ही जीवन है, और वर्षा जल का संरक्षण भविष्य की जरूरत है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में संचालित की जा रही अनेक गतिविधियां

जल संरक्षण के लिए जल संगोष्ठी आयोजित, जल संरक्षण की दिलाई शपथ

सीहोर (निप्र)। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले मे 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में जल संरक्षण से संबंधित अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तहत आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए दीवार लेखन, जागरूकता रैली, पोस्टर बैनर, ग्राम सभाएं, कलश यात्राएं सहित अनेकों गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

अभियान के तहत जिले के अनेक ग्रामों में कूप मरम्मत, तालाब जीर्णोद्धार, डैम की साफ-सफाई सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं तथा नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित खेत, तालाब, अमृत सरोवर, परकोलेशन टैंक, डगवेल, तालाब जीर्णोद्धार, जनभागीदारी के कार्य, कूप एवं बाउंड्री मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रमुख उद्देश्य जनभागीदारी से जल संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करना है।

इस अभियान के अन्तर्गत समाज की भागीदारी तथा और विभिन्न सहयोगी विभागो की समेकित पहल से मुख्यत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण, भूजल संवर्धन, पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार करना है।

इसके साथ ही जल स्त्रोत में प्रदूषण कम करना, साफ सफाई करना, पौधरोपण के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण एवं जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जल संगोष्ठी आयोजित, जल संरक्षण की दिलाई शपथ

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद द्वारा बुधनी में जल संरक्षण के लिए जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने जल संरक्षण के लिए कार्ड शीट पर चित्रों के माध्यम से जागरूक किया। इसी प्रकार जन अभियान परिषद सीहोर के सदस्यों द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम बमुलिया, बड़नगर, निपानियाकला में ग्रामवासियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई तथा दीवार लेखन, जन चौपाल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही ग्राम बमुलिया में 400 वर्ष पुरानी बावड़ी की साफ -सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर सीहोर विकासखंड समन्वयक श्री प्रदीप सिंह सेंगर, बुधनी विकासखंड समन्वयक इंदर सिंह निकुम सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

हीट स्ट्रोक के प्रकोप से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

सीहोर (निप्र)। जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान औसत से अधिक होने की संभावना है। इसके कारण अधिकांश भागों में लू (तापघात) हीट स्ट्रोक की की स्थिति निर्मित हो सकती है। जिले में संभावित लू के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए इससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए जिला स्तर पर जन समुदाय को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव के लिए आवश्यक सुझाव तथा निर्देश जारी किये गये है। इस संबध में सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशानुसार जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि लू के प्रबंधन के सभी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। बाह्य रोगी कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था के साथ ही ठंडे जल की व्यवस्था सुनिश्चित किया करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक चिकित्सालय एवं उप जिला चिकित्सालय 05 बिस्तरीय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 बिस्तर इन मरीजों के लिए आरक्षित किया करने के निर्देश दिए गए हैं।

हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय : हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ठंडे पानी और कूलर की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित करें। ढीले सूती कपड़े पहने। प्रभाव को कम करने के लिए विशेष प्रकार के सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें। जितना संभव हो सके त्वचा को साफ और शुष्क बना कर रखें, इससे संक्रमण की संभावना कम होती है। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ में लेकर जाए।

बुजुर्ग शांति बाई को कलेक्टर ने दिलाया न्याय, वर्षों पुरानी जमीन सम्बन्धी समस्या का तत्काल किया समाधान

बैतूल (निप्र)। घोड़ाडोंगरी पहुंचे कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने राजस्व विभाग की समीक्षा के साथ यहां जनसामान्य की समस्याएं भी सुनी। बड़ी आस लिए यहां पहुंची बुजुर्ग शांति बाई ने नम आंखों से अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। महिला ने बताया कि उनके परिजन द्वारा उनकी कृषि भूमि पर छल से जबरन कब्जा कर उन्हें कृषि कार्य नहीं करने नहीं दिया जा रहा है और चतुर सीमा गलत बताकर विक्रय कर दिया है। उनके मकान पर भी नहीं रहने दिया जा रहा है। उनकी भूमि पर उनके पोता सत्यम का नामांतरण आदेश के होने के बाद भी आज तक उनके नाती का नाम दर्ज नहीं किया गया हैं। महिला की समस्या को गंभीरता से सुन कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नामांतरण आदेश बुलवाया और आदेश अमल नहीं होने पर पटवारी को फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही शांतिबाई के नाती का नाम दर्ज करवाया और खसरा की कापी प्रदान की गई। यहीं नहीं बुजुर्ग महिला और उनके नाती को कलेक्टर ने अपने वाहन में सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके साथ उनकी ग्राम टैमरूरैयत स्थित कृषि भूमि पर पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन के दस्तावेज का अवलोकन किया जिसमें पाया कि चतुर्सीमा गलत लगाकर परिजन द्वारा विक्रय कर दी गई है जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को रजिस्ट्री दुरुस्त करवाने और सही चतुर सीमा अनुसार समान रूप से बंटवारा व नक्शा संशोधन किए जाने के निर्देश दिए। मौके पर कब्जा भी दिलवाया गया। इस दौरान महिला के खेत में कुआं क्षतिग्रस्त पाए जाने पर कलेक्टर ने मनरेगा योजना के तहत कुएं की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव को दिए। यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

मकान की मरम्मत कराने के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बुजुर्ग महिला के मकान का भी जायजा लिया। वर्षों से बंद मकान खुलवा कर मकान क्षतिग्रस्त पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मकान की मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जन सहयोग से मकान की छत बदले जाने का भी वादा किया। मकान के पीछे किया पड़ोसी का अतिक्रमण हटवाया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ भी चर्चा कर कहा कि ग्राम में शांतिबाई को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी उनका सहयोग करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल सूचना तहसील कार्यालय में दे।

शांति बाई ने सरकार का माना आभार

जमीन और मकान संबंधी बरसों पुरानी समस्या से जूझ रही शांति बाई का त्वरित समाधान होने पर बहुत खुश नजर आई, उन्होंने बताया कि वे कभी सोच भी नहीं सकती थी। उनकी समस्या का इतने जल्दी और गरिमा के साथ समाधान हो सकेगा। मैं और मेरा नाती शासन के आभारी हैं। इस दौरान शांतिबाई ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मन से याद किया।

सत्यम को मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ

कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शांति बाई के पोता सत्यम को भी महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उल्लेखनीय है कि शांति बाई के पोता सत्यम के पिता का असामायिक निधन हो गया था, जिसके बाद से ही सत्यम अनाथ हो गया। सत्यम का पालन पोषण शांतिबाई ही कर रही थी।

उच्च जोखिम गर्भवती महिला श्रीमती गीता सलामे का हुआ सुरक्षित प्रसव

बैतूल (निप्र)। भीमपुर विकासखंड के ग्राम पलासपानी की उच्च जोखिम गर्भवती महिला श्रीमती गीता सलामे का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमपुर में सुरक्षित प्रसव हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.राजेश परिहार ने बताया कि श्रीमती गीता पति श्री मुकेश सलामे निवासी ग्राम पलासपानी विकासखण्ड भीमपुर का गर्भावस्था का पंजीयन 12 सप्ताह के पहले 10 सितम्बर 2024 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती पारकला नर्रे द्वारा किया गया। पंजीयन के समय श्रीमती गीता का वजन 42 किलोग्राम, एचबी 11.2 ग्राम, बीपी 149/102 एवं एल्बुमिन शुगर एबसेन्ट दर्ज किया गया। श्रीमती गीता का ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कारण उन्हें हाईरिस्क गर्भावस्था की श्रेणी में रखा गया। श्रीमती गीता के हाई रिस्क होने के कारण आशा कार्यकर्ता श्रीमती कलावती सलामे द्वारा प्रतिमाह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व शिविर में लाकर नियमित जांच कराई गई तथा एएनएम श्रीमती परकला नर्रे द्वारा प्रतिमाह

आरोग्य केंद्र पर नियमित जांच की गई। श्रीमती गीता को आयरन, कैल्शियम की गोलियां खिलाई गईं तथा पोषण आहार, पर्याप्त आराम, नियमित जांच, नियमित दवाइयों के सेवन करने के बारे मे समझाइश दी गई। श्रीमती गीता की एलएमपी 24 जून 2024 एवं ईडीडी 31 मार्च 2025 के आधार पर आशा कार्यकर्ता श्रीमती कलावती सलामे के द्वारा प्रतिदिन निगरानी की गई। उन्हें 02 अप्रैल 2025 को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 जननी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर मे भर्ती कराया गया। श्रीमती गीता ने 03 अप्रैल 2025 को स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलो 700 ग्राम था। शिशु का जन्म के समय आवश्यक जीरो डोज टीकाकरण किया गया। 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के पश्चात् 05 अप्रैल 2025 को डिस्चार्ज किया गया। श्रीमती गीता को पोषण आहार, शिशु को टीकाकरण एवं परिवार नियोजन के साधन अपनाने के बारे में परामर्श दिया गया। डिस्चार्ज के समय श्रीमती गीता के परिवार वालो ने स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमपुर के बीएमओ डॉ दीपक निगवाल ने बताया कि यदि उच्च जोखिम गर्भावस्था के लक्षणों का ध्यान रखकर उपचार न किया जाए एवं स्वास्थ्य दल द्वारा सतत निगरानी तथा देखरेख में कमी की जाए तो गर्भवती महिला की जान भी जा सकती है इसलिये उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली प्रत्येक महिला को स्वास्थ्य दल का परामर्श मानकर नियमित उपचार लेना चाहिए।

कृषि वैज्ञानिक द्वारा पोषण पखवाड़ा के तहत सिराली मे प्रशिक्षण दिया गया

हरदा (निप्र)। कृषि विज्ञान केंद्र हरदा की गृह वैज्ञानिक सुश्री जागृति बोरकर द्वारा सिराली मे ग्रामीण माहिलाओं को पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में एनीमिया के कारण और इससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने एनीमिया से बचने हेतु सबसे सस्ते और घर घर में उपलब्ध रहने वाले स्त्रोत मुनगा पाउडर को उपयोग में लाने के तरीको से ग्रामीण माहिलाओं को अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने एनामिया से बचने के लिए महिलाओं को लोहे के बर्तन मे भोजन पकाने, अंजीर, गुड़ और पिंडखजूर आदि के उपयोग के संबंध में सलाह दी।

नरवाई जलाने की रोकथाम एवं प्रबंधन के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए आवश्यक निर्देश

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को नरवाई न जलाये जाने तथा प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में नरवाई जलाने की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के पश्चात भी किसानों द्वारा नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि वातावरण, मिट्टी की संरचना एवं पोषक तत्वों तथा उर्वरा शक्ति के लिए नुकसानदायक है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फायर मॉनिटरिंग वेबसाइट पर सभी सम्मिलित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों का अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिससे वन क्षेत्र एवं नरवाई जलाने संबंधी घटनाओं की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। जे फार्म एप पर जिले में उपलब्ध 75 सुपर सीडर का रजिस्ट्रेशन कराया जाए तथा जिले के सभी किसानों को जे फार्म एप पर जोड़कर सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले में पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं वन रक्षेक की संयुक्त टीम गठित कर संबंधित क्षेत्र में नरवाई एवं वन क्षेत्र में आग न लगाने के लिए प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा क्षेत्र में घटित होने वाले प्रकरणों में संबंधित किसानों के विरुद्ध पंचनामा तैयार कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही जिन ग्रामों में अभी फसल कटाई शेष है तथा पहले वर्ष में इन ग्रामों में नरवाई जलाने की घटनाएं हुई हों तो ऐसे ग्रामों में ट्रैक्टर चलित वाटर टैंकर (पम्प सहित) उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए, जिससे खड़ी फसल में आग ना लगे तथा नरवाई में लगी हुई आग को तत्काल बुझाया जा सके।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने चौपाल लगाकर किया ग्रामीणों से संवाद

रायसेन (निप्र)। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गुरूवार को सांची जनपद की ग्राम पंचायत वनगवां के ग्राम रतनपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर जाना कि उन्हें शासन की कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है।कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि शासन द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्रामीणों के पास पहुंचकर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीणजन भी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएं।

कलेक्टर श्री जैन ने दौरा कर नहरों से सिंचाई व्यवस्था का लिया जायजा

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को टिमरनी विकासखंड के ग्राम समरधा, अजनाई, गोंदागांव, अबगांव, व पोखरनी का दौरा कर वहां नहरों के माध्यम से मूंग फसल की सिंचाई के लिये की गई व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सुश्री सोनम बाजपेई, एसडीएम टिमरनी श्री महेश बडोले और तहसीलदार टिमरनी डॉ. प्रमेश जैन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।कलेक्टर श्री जैन ने भ्रमण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुश्री बाजपेई को निर्देश दिये कि सिंचाई कार्य के दौरान रात्रि में राजस्व व पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें। उन्होने कहा कि अवैध रूप से नहर का पानी लिफ्ट करने वालों तथा नहरों में हेडअप लगाकर पानी के प्रवाह को बाधित करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री जैन ने कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये कि ओसराबंदी लागू कर ऐलान क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिये पानी पहुँचाने की व्यवस्था करें।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत युवाओं ने ली जल संरक्षण की शपथ, बनाई मानव श्रृंखला

पानी की एक-एक बूंद को सहेजने का लिया संकल्प

बैतूल (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अभियान के तहत शुक्रवार को चिचोली, मुलताई, शाहपुर एवं आठनेर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझाया गया और उन्हें यह बताया कि किस प्रकार छोटे-छोटे प्रयासों से जल संकट से निपटा जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण के सरल और प्रभावी उपाय बताए गए, साथ ही जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। युवाओं को यह भी प्रेरित किया कि वे अपने-अपने गांवों व मोहल्लों में जल संरक्षण का संदेश फैलाएं और जनसहयोग से साफ-सफाई व जल स्रोतों के रखरखाव के लिए अभियान चलाएं। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के सामाजिक कार्यकर्ताओं, नवांकुर समितियां के प्रतिनिधियों एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ने मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली।

पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने की जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा

पेयजल समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत निराकरण करें : प्रमुख सचिव श्री नरहरि

सीहोर (निप्र)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री पी नरहरि की अध्यक्षता में सीहोर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के., जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्री पी नरहरि ने जिले में चल रहे नल जल योजनाओं के कार्यों कि विकासखण्डवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी ग्राम में पेयजल समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का तुरन्त निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद एवं पीएचई के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर भ्रमण करें और पेयजल समस्या निर्मित होने के पहले ही उचित कार्यवाही करे। बैठक में मुख्य अभियन्ता श्री आर. के. हिरोडिया, सभी जनपद सीईओ, जल निगम एवं पीएचई के अधिकारी उपस्थित थे।

राइट क्लिक

कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका- इस टकराव का अंजाम क्या होगा?

अजय बोकिल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयको को सम्बन्धित राज्यपालों द्वारा अनंत काल तक रोक कर 'पॉकेट वीटो' करने की प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, उससे विधायिका में भारी कसमसाहट है। सत्तापक्ष का मानना है कि यह कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप है। अदालतें कार्यपालिक प्रमुखो जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देशित कैसे कर सकती हैं। दूसरी तरफ न्यायपालिका का मानना है कि यदि कार्यपालिक प्रमुख अपने संवैधानिक दायित्वों की व्याख्या मनमाने और सियासी गुणा भाग के हिसाब से करेंगे तो न्यायपालिका को न्यायदंड अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के इस मामले में सरकार तो सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति भी हैं, ने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट सुपर संसद की तरह काम न करे। हालांकि उपराष्ट्रपति के इस तेवर पर भी विधि विशेषज्ञ दो खेमों में बंट गए हैं, एक इस पर आपत्ति जता रहा है तो दूसरा इसे 'साहसिक' बता रहा है। तो क्या अब संविधान के दो मूलभूत अंग न्यायपालिका और कार्यपालिका ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए सुखकर है? क्या इस सैद्धांतिक द्वंद्व का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा या फिर एक दूसरे की मुश्कें कसने की पूर्वपीठिका तैयार की जा रही है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि वैचारिक द्वंद्व होना अलग बात है और अधिकारों का अतिक्रमण और मर्यादा का सीमांकन की जिद होना दूसरी बात। इस द्वंद्व कार्यपालिका, विधायिका से समर्थन चाहेगी, जो हो भी रहा है। क्योंकि स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका (जो आज खुद सवालों के घेरे में है) अक्सर कार्यपालिका के कान उमेठती रहती है और कभी कभार विधायिका को भी निर्देशित करती है।

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल रवि के मामले में स्पष्ट फैसला देते हुए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी की समय सीमा 3 माह तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि इस समयावधि में राज्यपाल विधेयक पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें स्वत- कानून माना जाए। लिहाजा तमिलनाडु में ऐसे 10 विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून बन चुके हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति है। यही नहीं न्यायपालिका ने राज्यपालों के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा भी किसी विधेयक पर मंजूरी की समयावधि तीन माह तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ द्वारा दिए गए इन फैसलों को एक वर्ग न्यायपालिका द्वारा अपनी मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देख रहा है तो समाज का दूसरा वर्ग इसे न्यायपालिका की सक्रियता और निर्भीकता का प्रमाण मान रहा है। इस दूसरे वर्ग का मानना है कि अब लोकतंत्र बचने की आस केवल न्यायपालिका से ही है, क्योंकि बाकी दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओंने सत्तातंत्र की दबंगई के आगे घुटने टेक दिए हैं। जबकि सत्तातंत्र जिसमें विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका भी शामिल है, इसे अपने अस्तित्व और वैधता पर न्यायपालिका का स्पष्ट अतिक्रमण मान रही है, जोकि पूरी तरह अस्वीकार्य है। सर्वोच्च अदालत से इस फैसले से सरकार विचलित है। बताया जाता है कि वह जल्द ही इस फैसले पर सुधार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। लेकिन यदि कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखा तो क्या सरकार उसे खारिज करने क्या सरकार नया कानून संसद से पास कराएगी?

यूं यह कानूनी और संवैधानिक बहस का मुद्दा है कि भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों की लक्ष्मण रेखाएं कहां तक हैं? कहां उनका अतिक्रमण होता है और कहां वो शीलभंग के दायरे में हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए? खास कर उस दौर में जहां न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में हो, विधायिका और कार्यपालिका खुद को सर्वेसर्वा मानने लगे।

भारतीय संविधान मूल रूप से तीन पहियों की गाड़ी पर चलता है। ये हैं, विधायिका, जो देश के लिए कानून बनाती है, न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है और उसका पालन करवाने की समीक्षा करती है, और कार्यपालिका जिसका काम कानून पर अमल करवाना है। संविधान में ये तीनो अपने आप में स्वतंत्र लेकिन परस्पर जवाबदेह तथा एक दूसरे को संतुलित करने वाली सत्ताएं हैं। न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं है कि वह विधायिका की जगह ले ले या फिर कार्यपालिका ही किसी कानून की मनमानी व्याख्या करने लगे। कार्यपालिका, जिसके पास वास्तविक सत्ता और अधिकार होते हैं, वह विधायिका और न्यायपालिका दोनो के प्रति जवाबदेह है।

संविधान में राज्यपाल को राज्य का संरक्षक माना गया है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में राज्यपाल दिल्ली सरकार के एजेंट की तरह ही व्यवहार करते हैं और केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के अजेंडे को प्राथमिकता से पूरा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। दिक्कत तब होती है, जब राज्य में विपक्षी पाटी की सरकार होती है। वहां राज्यपालों का व्यवहार राज्य के अभिभावक की तरह कम एक राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोकना और रोकने का कारण भी न बताना संवैधानिक खामियों और राजनीतिक स्वार्थों की वजह भले गलत न लगे, लेकिन राज्यपाल की नीयत पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 'अति सक्रियता' का परिचय देते हुए राज्य और देश के संवैधानिक प्रमुखों की जवाबदेही और समयसीमा तय कर दी। अर्थात यह काम राज्य प्रमुखों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि विधानसभा द्वारा पारित बिल के मामले में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो (पॉकेट वीटो) का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नैतिक रूप से विपक्षी पार्टियों की जीत है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिफरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कुछ बुनियादी संवैधानिक सवाल उठाए हैं, जिनके उत्तर अपेक्षित हैं। उपराष्ट्रपति ने बिलों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा के प्रशिक्षुओ के कार्यक्रम में कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। आज जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। जबकि सभी को अपनी अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ही सबसे अहम होती है। सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका द्वारा दूसरे के मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि खुद न्यायपालिका का अपने मामलो में आचरण क्या है? दिल्ली में जस्टिस यशंवत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों? जबकि जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट बरामद हुए थे। ये किसके थे, कहां से आए, कौन और क्यों लाया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं, जिनसे न्यायपालिका के भीतर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को और खाद-पानी मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर जस्टिस की जगह यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ कई जांच एजेंसियां सक्रिय हो जातीं।

जाहिर है कि विधायिका को न्यायपालिका द्वारा उसकी हदें तय करने के फैसले ने विचलित कर दिया है। लेकिन विधायिका की भी कोई जवाबदेही न हो, यह भी उचित नहीं है। इस बात का जवाब अक्सर इस दलील से दिया जाता है कि जनप्रतिनिधियों को हर पांच साल में जनता के बीच जाकर परीक्षा देनी होती है, उसे पास करना होता है। जबकि न्यायपालिका को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोग अदालतों की न्यायदान प्रक्रिया और वास्तविक इंसाफ पर नजर नहीं रखते। सच्चा और निष्पक्ष न्याय हो, समय पर हो और न्याय होता हुआ दिखे भी यही न्यायपालिका की लोकतांत्रिक कसौटी है। लेकिन विधायिका और न्यायपालिका किसी गलती या कर्तव्यपालन में खामी के लिए एक दूसरे को न टोकें, यह भी सही नहीं है। क्योंकि दोनो संविधान और उसकी भावना की रक्षा करने की जिम्मेदारी समान रूप से दोनो की है।

उपराष्ट्रपति ने एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति को निर्देशित करने पर उठाया है। उन्होंने कहा कि अदालत राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में कोई काम करने के लिए कैसे निर्देशित कर सकती है? विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया तय है, लेकिन यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी करना अनिवार्य है, ऐसा उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। यही तर्क केरल के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए दिया था। मगर यहां सवाल केवल समय सीमा भर का नहीं है, बल्कि मंशा का है। यदि कोई बिल राज्यपाल के अधिकार कम करता हो तो भी राज्यपाल को संवैधानिक प्रक्रिया से ही काम करना होगा। क्योंकि उसे मंत्रि परिषद की सलाह से ही काम करना है। अगर राज्यपाल की मंशा ऐसे किसी बिल को लटकाने की है तो राज्य सरकार और विधानसभा क्या करे? संविधान अपनी संस्थाओंको विवेक से काम करने की आजादी तो देता है, लेकिन मनमर्जी और राजनीतिक दुराग्रह से काम करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्यपालों का व्यवहार आज ही देखने में आ रहा है। पहले भी कुछ राज्यपालो का आचरण दिल्ली के सत्ताधीशों के सियासी हितों साधने से प्रेरित रहा है। इनके आचरण से राज्यपाल संस्था की गरिमा को बट्टा ही लगा।

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

॥ मंदिरम् ॥ 88

वीर नारायण मंदिर, कर्नाटक

वीर नारायण मंदिर, जिसे बेलवाडी के वीरनारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, एक जटिल होयसला वास्तुकला वाला एक ट्रिपल हिंदू मंदिर है जो लगभग 1200 ईस्वी में पूरा हुआ था। हलेबिदु के करीब, यह एक बेहतर संरक्षित बड़ा होयसला स्मारक है जो भारत के कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के छोटे से गाँव बेलवाडी में पाया जाता है। मंदिर में तीन अलग-अलग वर्गाकार गर्भगृह हैं जो एक असामान्य रूप से बड़े वर्गाकार रंग-मंडप (103 फीट) के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मुख्य मंदिर पूर्व की ओर है और वीरनारायण (विष्णु) को समर्पित है। उत्तर की ओर वाला मंदिर गोपाल को समर्पित है, जबकि दक्षिण की ओर वाला मंदिर योग-नरसिम्हा के लिए है। 14वीं शताब्दी में क्षतिग्रस्त होने से पहले मंदिर का संभवतः कई चरणों में विस्तार किया गया था, और इसे और अधिक विनाश से बचाने के लिए इसमें कुछ विशेषताएं जोड़ी गई थीं। तारकीय शैली के इस मंदिर की उल्लेखनीय विशेषताओं में आभूषण जैसे विवरण के साथ इसकी उत्कृष्ट रूप से अलंकृत वेसरा अधिरचना (शिकार) शामिल हैं। अंदर खंभों की बारीक पॉलिश वाली आकाशगंगा है, कुछ बैंड वाले हैं जैसे कि उन्होंने गहने पहने हों। छत पर भी कृष्ण के बारे में हिंदू किंवदंतियों को दर्शाने वाली आलंकारिक झांकियों के असामान्य पैनल हैं।

गांधीसागर पहुंचे चीता पावक और प्रभास सीएम डॉ. मोहन यादव ने बाड़े में छोड़ा

मंदसौर (नप्र)। कूनो से दोनों चीते प्रभाष और पावक रविवार दोपहर 3 बजे गांधीसागर खेमला अपने नए घर पहुंचे थे। उनको शाम 5.35 बजे तक उनके लिए बनाए गए बाड़े में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छोड़ा। प्रभाष और पावक की उम्र 6 साल है, ये अफ्रीका में पैदा हुए हैं। सीसीएफ ने बताया कि तीन बजे दोनों चीते गांधीसागर पहुंचे। उनको शाम को 5.35 बजे मुख्यमंत्री ने बाड़े में छोड़ा। चीतों के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थी।

चीतों पर रखी जाएगी 24 घंटे नजर–16.4 वर्ग किलोमीटर के बाड़े हैं। 24 घंटे उन पर निगरानी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य को लेकर भी टीम की नियुक्ति की गई है।

2 चीतों के छोड़े जाने पर दी प्रदेश के नागरिकों को बधाई, मप्र का वातावरण हैं चीतों के अनुकूल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के छोड़े जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गाँधी सागर अभयारण्य में 2 चीते छोड़े जाने का अवसर प्रसन्नता का विषय है। इस लुप्त प्रायः प्रजाति के वन्य प्राणी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से सितंबर 2022 में मध्यप्रदेश में पहली बार लाया गया था। अब इन चीतों का कुनबा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदसौर जिले के गाँधी सागर अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। चीता प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य भारत में चीतों की संख्या बढ़ाना और उनकी प्रजाति को बचाना है। इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। गाँधी सागर अभयारण्य प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थान है, जहाँ चीतों को बसाया जा रहा है। वन्य जीव पर्यटन की दृष्टि से आज एक ऐतिहासिक दिन है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका, केन्या और बोत्सवाना से चीतों को लाकर मध्यप्रदेश के जंगलों में बसाया जा रहा है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 26 चीते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में भी चीता पुनर्स्थापन के प्रयास हुए लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल सकी। भारत में यह प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। यहां चीतों की सर्वाइवल की दर अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश के वन और वातावरण चीतों के अनुकूल है। प्रदेश में कूनो के बाद गांधी सागर भी इनका घर बन रहा है। गाँधी सागर पश्चिमी मध्यप्रदेश में स्थित एक वन्य अभयारण्य है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अभयारण्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में मंदसौर और नीमच जिले में फैला हुआ है। कई सौ साल पहले क्षेत्र में जरूर चीते रहे भी होंगे। विलुप्त होने के वर्षों बाद अब उनका पुनः आगमन वन्य जीव पर्यटन के लिए भी शुभ है।

दमोह में खाली पार्सल ट्रेन पटरी से उतरी

दो यात्री ट्रेनें रुकीं,हादसा टला

दमोह (नप्र)। दमोह रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मलैया मिल रेलवे फाटक के पास दोपहर करीब 3:00 बजे कटनी से बीना जा रही एक खाली पार्सल ट्रेन की तीन बोगियों के पहिए पटरी से उतर गए। ट्रेन खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेल विभाग के टेक्निकल प्रभारी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। कलेक्टर सुधीर कोचर के निर्देश पर तहसीलदार मोहित जैन भी स्थिति का जायजा लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

यात्री ट्रेन प्रभावित हुई

हादसे के कारण यात्री सुविधा प्रभावित हुई है। कटनी से आ रही गोंडवाना एक्सप्रेस और बीना मेमू ट्रेन को रोकना पड़ा। रेल अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक क्लियर होने के बाद ही इन ट्रेनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

रेस्क्यू के लिए कटनी से विशेष ट्रेन भेजी

उपकरणों से लैस एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई है। इन उपकरणों की मदद से पटरी से उतरी बोगियों को वापस ट्रैक पर लाया जाएगा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पार्सल ट्रेन तीसरी लाइन से मेन ट्रैक पर शिफ्ट होते समय यह हादसा हुआ।

कही-सुनी

रवि भोई
(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

सुकमा से उठा बवंडर क्या गुल खिलाएगा ?

नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में तेंदूपत्ता संग्राहकों का बोनस अफसरों द्वारा हजम करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों डीएफओ अशोक पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरकार ने पहले ही अशोक पटेल को सस्पेंड कर दिया था। अशोक पटेल 2015 बैच के प्रमोटी आईएफएस हैं। संग्राहकों के बोनस में हेरफेर का मामला है तो 2021-2022 का, पर उजागर हुआ 2024 में। पूरे मामले को उठाया पूर्व विधायक और कम्युनिष्ट नेता मनीष कुंजाम ने। मनीष कुंजाम ने कई सवाल उठाए हैं और एक वरिष्ठ आईएफएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष कुंजाम के कहे अनुसार वरिष्ठ आईएफएस राजनीतिक काम करने के अभियान में लगे थे। सुकमा आदिवासी बहुल है,जिनका जीवन यापन वनोपज पर ही टिका है। वैसे में आदिवासियों का ही जेब काट लेना कितनी गजब बात है ? पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के लिए लागू कुबेर प्रणाली के बाद भी करोड़ों रुपए का खेल होना, बड़े ही ताज्जुब की बात है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सुकमा से कांग्रेस के विधायक हैं और सुकमा जिला पंचायत पर भी कांग्रेस का कब्जा है। क्या इस कारण भाजपा की सरकार ने सुकमा के लिए आँखें बंद कर ली ,जबकि वन मंत्री केदार कश्यप स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं और बस्तर इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। वनमंत्री के नाक के नीचे ऐसा कैसे हो गया, चर्चा का विषय है। लोग कह रहे हैं कि मनीष कुंजाम शिकायत नहीं करते तो क्या गड़बड़ी सामने नहीं आती? बताते हैं भाजपा के एक नेता डीएफओ अशोक पटेल को सुकमा से बीजापुर ले जाने की जुगत में थे, पर बोनस कांड के चलते मामला लटक गया। अशोक पटेल के लिए सिफारिश होने लगी तो एक सीनियर अफसर ने उन्हें सस्पेंड ही कर दिया। सरकार एक तरफ बस्तर को नक्सल मुक्त करने में लगी है। नक्सलियों की पूरी फंडिंग खत्म करना चाहती है ऐसे में सुकमा कांड कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आदिवासियों के हक के पैसे को आखिर डीएफओ अशोक पटेल ने कहां खपाया ?

सीजीएमएससी मामले में तीन और आईएएस को बुलावा

कहते हैं सीजीएमएससी मामले की जाँच पड़ताल में ईओडब्ल्यू ने राज्य के तीन और आईएएस को नोटिस भेजा है। ये तीनों आईएएस अफसर किसी न किसी दौर में सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक रह चुके हैं। ईओडब्ल्यू इस मामले में पहले ही दो आईएएस से घंटों पूछताछ कर चुकी है। दवाई और उपकरण खरीदी मामले में गड़बड़ी के आरोप में सीजीएमएससी के कुछ अफसर और एक सप्लायर जेल में भी हैं। सीजीएमएससी में दवा घोटाले का तार घूमता ही जा रहा है और कई लोग लपेटे में आ रहे हैं। अब लोगों को इंतजार है कि ईओडब्ल्यू दवा घोटाले में किस-किस को और कितने को लपेटे में लेती है। दवा घोटाले में तीन आईएएस को नोटिस से अफसरों में खलबली मची है।

आबकारी सचिव आर.संगीता छुट्टी पर जाएंगी

चर्चा है कि राज्य की आबकारी सचिव आर.संगीता 24 अप्रैल से तीन महीने की छुट्टी पर जाएंगी। बताते हैं वे अमेरिका जा रही हैं। आर.संगीता की छुट्टी की खबरों के बीच नए आबकारी सचिव के नाम का कयास भी लगाया जाने लगा है। माना जा रहा है कि तीन महीने के लिए किसी आईएएस को आबकारी विभाग का प्रभार दे दिया जाएगा। सुगबुगाहट है कि आबकारी विभाग का चार्ज तीन महीने के लिए मुकेश बंसल को दिया जा सकता है। मुकेश बंसल के पास अभी वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग है। आर.संगीता और मुकेश बंसल 2005 बैच के अफसर हैं।

दिल्ली से तय होगा नए मुख्य सचिव का नाम

अमिताभ जैन की जगह मुख्य सचिव के लिए सुब्रत साहू, रेणु पिल्लै, अमित अग्रवाल और मनोज पिंगुआ के नाम अभी भले तैर रहे हों, पर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव का नाम दिल्ली से ही तय होगा। अमिताभ जैन जून में रिटायर होने वाले हैं, पर मुख्य सूचना आयुक्त की दौड़ में होने के कारण उनके समय से पहले रिटायर होने के संकेत हैं। अमिताभ जैन के बाद रेणु पिल्लै वरिष्ठ हैं, उसके बाद सुब्रत साहू का नंबर है। अमित अग्रवाल दिल्ली में पोस्टेड हैं। चीफ सेक्रेटरी चयन मामले में भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के अनुभव का बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी का फैसला भी दिल्ली से ही होगा।

आकाश तिवारी की ऊँची छलांग

रायपुर नगर निगम के पार्षद आकाश तिवारी ने ऐसी छलांग लगाई कि कांग्रेसी देखते ही रह गए। आकाश तिवारी को कांग्रेस नेताओं ने पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी लायक ही नहीं समझा था, पर ऐसी गोटी फिट की कि उनकी कांग्रेस में इंट्री भी हो गई और कांग्रेस पार्षद दल के नेता याने नेता प्रतिपक्ष बन गए। आकाश तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़कर नगर निगम पहुंचे,फिर उनके लिए रास्ता बनता गया। कांग्रेस ने पहले संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। एक सामान्य सभा की बैठक में उन्होंने भूमिका भी निभाई। इसके बाद कांग्रेस ने संदीप साहू की जगह आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बताते हैं आकाश तिवारी ने दिल्ली से चाल चली और उसमें कामयाब रहे। प्रदेश ईकाई देखती रह गई। अब दिल्ली के फैसले को पलटने का साहस राज्य के नेताओं में दिखता नहीं है। भले संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का साहू समाज विरोध कर रहा है।

मंत्री जी के पीए की करतूत

कहते हैं राज्य के एक मंत्री जी के पीए साहब ट्रांसफर के नाम पर आदेश से पहले अपनी जेब गर्म कर ली। कई लोगों ने पीए साहब को एडवांस में राशि दे दी। मंत्री जी के यहां से ट्रांसफर का प्रस्ताव मंत्रालय को चला गया। ट्रांसफर चाहने वाले नक्सली इलाके से निकलना चाहते थे, उनके बदले वहां कोई जा नहीं रहा था। इससे मामला उलझ गया। बताते हैं मंत्री के प्रस्ताव पर एक अफसर ने लंबी टीप लिखकर फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मामला पता चलने पर मंत्री जी ने पीए को तो हटा दिया, लेकिन पीए साहब अब भी तबादला आदेश निकलवाने में जुटे हैं और अन्यंत्र ट्रांसफर के बाद भी मंत्री जी के बंगले में नजर आते हैं। ट्रांसफर लिस्ट निकलवाना पीए साहब की मजबूरी है, क्योंकि एडवांस में अपनी जेब गर्म कर ली है। चर्चा है कि महीनों बाद ट्रांसफर आदेश नहीं मिलने पर एडवांस देने वाले पीए साहब पर चढ़ाई भी शुरू कर दी है।

दो एसपी के केंद्र में जाने की चर्चा

धमतरी के एसपी आंजनेय वार्ष्णेय और नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार के भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की चर्चा है। आंजनेय वार्ष्णेय 2018 बैच के आईपीएस और प्रभात कुमार 2019 बैच के आईपीएस हैं। दोनों आईपीएस को विष्णुदेव साय की सरकार ने ही जिलों में एसपी के तौर पर पदस्थ किया है। कुछ महीने पहले धमतरी की कलेक्टर रहते नम्रता गाँधी और दुर्ग की कलेक्टर रहते ऋचा प्रकाश चौधरी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चलीं गईं। वैसे कलेक्टर रहते आईएएस और एसपी रहते आईपीएस भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाते। यह नया ट्रेंड है।